रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-73

REGISTERED No. D. (D)-73

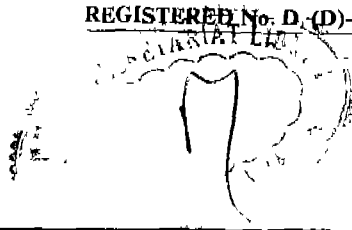

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 20] नई दिल्ली, शनिवार, मई 20, 1978/वैशाख 30, 1900
No. 20] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 20, 1978/VAISAKHA 30, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 3 मार्च, 1978

(आय-कर)

का०आ० 1397.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80 छ की उपधारा 2(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "श्री लक्ष्मी नरसिम्हा देवालय, मार्गाओ—गोवा" को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए गोवा संघ राज्य क्षेत्र में सर्वत्र विख्यात लोक पूजा का स्थान अधिसूचित करती है ।

[सं० 2208/फा० सं० 176/129/77-आई०टी० (ए I)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 3rd March, 1978

(INCOME TAX)

S.O. 1397.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2)(b) of Section 80-G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Shri Laxminarcinva Devalaya, Margao-Goa" to be a place of public worship of renown throughout the Union Territory of Goa for the purposes of the said Section.

[No. 2208/F. No. 176/129/77-IT(AI)]

नई दिल्ली, 29 मार्च, 1978

आय-कर

का०आ० 1398.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "फ्रांसिस्कन जूनियरेट होम सोसायटी" को निर्धारण वर्ष 1976-77 के लिए और से उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है ।

[सं० 2233/फा० सं० 197/47/77—आ०क० (ए I)]

New Delhi, the 29th March, 1978

(INCOME TAX)

S.O. 1398.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Society of the Franciscan Juniorate Home" for the purpose of the said section for and from the assessment year 1976-77.

[No. 2233/F. No. 197/47/77-IT(AI)]

आय-कर

का०आ० 1399.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "मैसूर डायोसेसन सोसायटी, मैसूर" को निर्धारण वर्ष 1977-78 के लिए और से उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है ।

[सं० 2235/फा० सं० 197/163/77-आ०क० (ए I)]

(INCOME TAX)

S.O. 1399.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies 'Mysore Dioccsan Society, Mysore' for the purpose of the said section for and from the assessment year 1977-78.

[No. 2235/F. No. 197/163/77-IT(AI)]

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1978

आय-कर

का०आ० 1400.—केन्द्रीय सरकार आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उप धारा (23-ग) के खड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "अरुलमिगु नेल्लाइप्पर और कान्तीमथी अम्बल, मन्दिर" को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए निर्धारण वर्ष 1974-75 के लिए तथा उस वर्ष से अधिसूचित करती है ।

[सं० 2240/फा० सं० 197/108/76-आ० क० (ए I)]

New Delhi, the 31st March, 1978

(INCOME TAX)

S.O. 1400.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies 'Arulmighu Nellaiappar and Kanthimathi Ambal, Temple" for the purpose of the said section for and from the assessment year(s) 1974-75.

[No. 2240/F. No. 197/110/77-IT(AI)]

आय-कर

का०आ० 1401.—केन्द्रीय सरकार आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "श्री सनातन रामा स्वामी मन्दिर, श्री काशी विश्वनाथ स्वामी मन्दिर और श्री बीर अंजनेय स्वामी मन्दिर" को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए निर्धारण वर्ष 1973-74 के लिए तथा उस वर्ष से अधिसूचित करती है ।

[सं० 2241/फा० सं० 197/114/77-आ०क० (ए I)]

(INCOME TAX)

S.O. 1401.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sri Santhanaramaswami Temple, Sri Kasi Viswanatha Swami Temple and Sri Veera Anjaneyaswami Temple" for the purpose of the said section for and from the assessment year(s) 1973-74.

[No. 2241/F. No. 197/114/77-IT(AI)]

आय-कर

का०आ० 1402.—केन्द्रीय सरकार आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80छ की उपधारा (2)(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "श्री वशिष्टेश्वरार मन्दिर, थित्तई, जिला थंजावुर" को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए तामिलनाडु राज्य में सर्वत्र विख्यात लोक पूजा का स्थान अधिसूचित करती है ।

[सं० 2250/फा० सं० 176/26/78-आ० क० (ए I)]

एम० शास्त्री, अवर सचिव

(INCOME TAX)

S.O. 1402.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2)(b) of Section 80G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sri Vasishteshwarar Temple, Thittai, Thanjavur District" to be a place of public worship of renown throughout the state of Tamil Nadu for the purposes of the said section.

[No. 2250/F. No. 176/26/78-IT(AI)]

M. SHASTRI, Under Secy.

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्ता का कार्यालय गुन्टुर

गुन्टुर, 7 जनवरी, 1978

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

का०आ० 1403—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 1944 के नियम 5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, इस अधिसूचना द्वारा, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 में बताए गए पद के अधिकारियों को, उनके अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली के नियम 173 आर० के० (2) के अन्तर्गत तथा उक्त सारणी के स्तंभ 4 में बतायी गई सीमाओं तथा शर्तों के अधीन उन मामलों के सम्बन्ध में हुए विलम्ब को, जहां पर कर निर्धारिती नियम 173 आर० डी० (2) के अन्तर्गत निर्दिष्ट अवधि के अन्दर-अन्दर शुल्क दायित्व का भुगतान नहीं कर पाता, दरगुजर करने से सम्बन्धित समाहर्ता की शक्तियों के प्रयोग का अधिकार प्रदान करता हूं ।

क्रम सं०	अधिकारी का पदनाम	के० उ० शु० नियम सं०	शर्तें तथा सीमाएं
1	2	3	4
1.	अधीक्षक	173 आर० के० (2)	6 दिन तक की देरी को दरगुजर करने के लिए।
2	सहायक समाहर्ता	173 आर० के० (2)	इसके अतिरिक्त और एक महीने के विलम्ब को दरगुजर करने के सम्बन्ध में ।

[अधिसूचना सं० 1/78 सी० सं० IV /8/1/78/एम० पी० 2]

Office of the Collector of Central Excise, Guntur

Guntur, the 7th January, 1978

CENTRAL EXCISES

S.O.1403.—In exercise of the powers vested in me under Rule 5 of Central Excise Rules, 1944, I empower the officers of the rank mentioned in Column 2 of the table appended below to exercise within their respective jurisdiction the powers of the Collector under Rule 173RK(2) of the Central Excise Rules, 1944, relating to condonation of delay in cases where the assessee fails to discharge the duty liability within the time specified under Rule 173RD(2), subject to the conditions and limitations indicated in column 4 thereof :

Sl. No.	Designation of the Officer	Central Excise Rule No.	Conditions and limitations
1	2	3	4
1.	Superintendent	173RK(2)	For condoning delay upto 6 days.
2.	Assistant Collector	173RK(2)	For condoning delay further upto one month.

[Notification No. 1/78/C. No. IV/8/1/78 M.P. 2]

गुन्टुर, 2 जनवरी, 1978

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

का०आ० 1404—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 1944 के नियम 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, इस अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के उन सभी अधिकारियों को, जिनका पद सहायक समाहर्ता के पद से निचली श्रेणी का नहीं है, अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में उक्त नियमावली के नियम 19-क के अन्तर्गत समाहर्ता की शक्तियों के प्रयोग का अधिकार प्रदान करता हूं ।

[अधिसूचना सं० 2/78/सी० सं० V (18ए) 8/62/77-एम० पी० 4]

Guntur, the 20th January, 1978

CENTRAL EXCISE

S.O. 1404.—In exercise of the powers vested in me under Rule 5 of Central Excise Rules, 1944, I empower all the Officers not below the rank of the Assistant Collector of Central Excise to exercise within their respective jurisdictions the powers of the Collector under Rules 49-A of the Central Excise Rules, 1944.

[Notification No. 2/78/C. No. V(18A) 8/62/77 MP. 4]

गुन्टुर, 28 जनवरी, 1978

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

का०आ० 1405—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 173 जी० के उप नियम (4) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त तथा दिनांक 25-1-78 की अधिसूचना सं० 10/78 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, द्वारा यथाप्रवर्तित, शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, इस अधिसूचना द्वारा निदेश देता हूं कि जो टैरिफ मद सं० 6, 7 8, 9, 10, 11, 11ए, 11-सी, 14-ए, 14-एच एच, 15बी, 16ए ए, 22-सी, 23, 27ए, 28, 33एए, 33डी डी, 34बी, 37-1, 63, 64, 66, 67 के अन्तर्गत आने वाले उत्पाद शुल्क्य माल का निर्माण करने वाले निर्धारितियों एवं टैरिफ मद सं० 11 बी०, 25, 26, 26ए, 26एए, 26बी, 27, 34 के अन्तर्गत आने वाले उत्पाद शुल्क्य माल का मुख्य रूप से उत्पादन करने वाले निर्धारितियों द्वारा, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली के नियम 173-जी के खण्ड (क) के अन्तर्गत तथा खण्ड (ख) में बताए गए उपबन्धों के अनुसार रखी जाने वाली लेखाबहियों को सम्बन्धित प्रयोजनों के लिए उचित प्रपत्र में रखी जाने वाली लेखाबही समझा जाएगा ।

2. इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ केवल नीचे बतायी गई विधि के अनुसार निर्माण करने वाले निर्धारितियों को सम्बन्धित उत्पाद शुल्क्य माल का "मुख्य उत्पाद" समझा जाएगा यदि,

(i) टैरिफ मद सं० 11 बी के बारे में वे माल जो मुख्य कच्ची सामग्री के रूप में कच्चा खनिज तेल काम में लाने वाले कारखानों में उत्पादित किए जाते हैं,

(ii) टैरिफ मद सं० 25, 26, 26ए, 26एए, 26बी और 27 के अन्तर्गत आने वाले वे माल, जो विशुद्ध धातु के निर्माण में कच्ची धातु का मुख्य कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग करने वाले कारखानों में तैयार किए जाते हैं ,

(iii) टैरिफ मद संख्या 34 के बाबत, ट्रेलर और शैसेइज के अलावा ऐसे सभी उत्पादित माल (कारखाने में जिनका एक माल उत्पाद किया जाता है) ।

3. यह अधिसूचना पहली फरवरी, 1978 से लागू होगी ।

[अधिसूचना सं० 3/78/फा० सं० IV/16/7/78-एम०पी०-2]

सी० भुजंगस्वामी, समाहर्ता

Guntur, the 28th January, 1978

CENTRAL EXCISE

S.O. 1405.—In exercise of the powers vested in me by Clause (c) of Sub-Rule (4) of Rule 173-G of Central Excise Rules, 1944, as introduced by Notification No. 10/78-Central Excises, dated 25-1-78, I hereby direct that all books of accounts maintained, under clause (a) of Sub-Rule (4) of Rule 173-G of Central Excise Rules shall, subject to provisions of Clause (b) of the said Rule, by assessees, who manufacture excisable goods falling under Tariff Item Nos. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11-A, 11-C, 14A, 14HH, 15B, 15AA, 22C, 23, 27A, 28, 33AA, 33DD, 34B, 37-I, 63, 64, 66, 67 and who are Main Producers of excisable goods falling under Tariff Item Nos. 11B, 25, 26, 26A, 26AA, 26B, 27 and 34, be deemed to be proper form for the respective purposes.

2. For the purpose of this notification, the producers will be treated as "Main Producer", if,

(i) in respect of Tariff Item No. 11B. the goods are produced in a factory making use of crude mineral oil as the main raw material ;

(ii) in respect of Tariff Item Nos. 25, 26, 26A, 26AA, 26B & 27, the goods are produced in a factory making use of mineral ore as the main raw material for the production of the virgin metal ; and

(iii) in respect of Tariff Item No. 34, the goods produced are other than trailer or chassis of a trailer (exclusively produced in a factory).

3. This shall come into force on the 1st day of February, 1978.

[Notification No. 3/78/File No. IV/16/7/78-MP. 2]

C. BHUJANGASWAMY, Collector.

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय, इलाहाबाद

इलाहाबाद, 12 अप्रैल, 1978

का०आ० 1406—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 173 आर०के० (2) के अन्तर्गत मुझे प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एतद्द्वारा शुल्क में देरी को माफ करने से सम्बन्धित उन मामलों में समाहर्ता की शक्तियों को नीचे लिखे अधिकारियों को प्रत्यायोजित (डेलीगेट) करता हूं जिनमें शुल्क निर्धारिती नियम 173 आर०के० (2) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट समय में शुल्कदायित्व को पूरा करने में असफल रहते हैं:—

(क) अधीक्षक	छह (6) दिन तक की देर को माफ करने का अधिकार
(ख) सहायक समाहर्ता	इससे अधिक एक माह तक की देर को माफ करने का अधिकार ।

[अधिसूचना सं० 2/78/पत्र-संख्या-IV (16) 171-नीति/77/8549]

अमृत लाल नन्दा, समाहर्ता

Central Excise Collectorate, Allahabad

Allahabad, the 12th April, 1978

S.O. 1406.—In exercise of the powers vested in me under Rule 173-RK (2) of the Central Excise Rules 1944, I hereby delegate the powers of the Collector, relating to condonation of delay in cases where the assessee fails to discharge the duty liability within the time specified under rule 173-RD (2) as under :—

(a) Superintendents.—For condoning delay upto 6 days.

(b) Assistant Collector.—For condoning delay further upto one month.

[Notification No. 2/78/C. No. IV(16)171--Pol/77/8549]

A. L. NANDA, Collector.

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय, पटना

पटना, 18 अप्रैल, 1978

का०आ० 1407—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनो के लिए प्रयोग) नियम 1976 के नियम 10 के उप-नियम 4 के अनुसरण में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क समाहर्तालय, पटना तथा इसके निम्नलिखित प्रमण्डल कार्यालयो को, जिसके कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है अधिसूचित करती है ।

1. प्रमण्डल कार्यालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क—	गया
2. प्रमण्डल कार्यालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क—	मुजफ्फरपुर
3. प्रमण्डल कार्यालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क—	लहेरियासराय
4. प्रमण्डल कार्यालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	पटना
5. प्रमण्डल कार्यालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	रांची
6. प्रमण्डल कार्यालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	पूर्णिया
7. प्रमण्डल कार्यालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	धनबाद

[सं० म० II(7) 2–हिन्दी प्रगति/76]

Office of the Collector of Central Excise, Patna

Patna, the 18th April, 1978

S.O. 1407.—In pursuance of sub-rule (4) of rule 10 of the Official Languages (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the Office of the Collector of Central Excise, Patna and its following Divisional Offices, the staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi :—

1. Divisional Office Central Excise.	Gaya
2. Divisional Office Central Excise.	Muzaffarpur
3. Divisional Office Central Excise.	Laheriasarai
4. Divisional Office Central Excise.	Patna
5. Divisional Office Central Excise.	Ranchi
6. Divisional Office Central Excise.	Purnea
7. Divisional Office Central Excise.	Dhanbad

[C. No. II(7)2-Hindi(Pro.)/76]

समाहर्ता सीमा शुल्क (निवारण) भारत-नेपाल सीमा का कार्यालय

पटना

का०आ० 1408.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में समाहर्ता सीमा-शुल्क (निवारण) भारत-नेपाल सीमा का कार्यालय पटना तथा इसके निम्नलिखित प्रमण्डल कार्यालयों को, जिसके कर्मचारिवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है ।

1. प्रमण्डल कार्यालय, सीमा शुल्क (निवारण)—	मुजफ्फरपुर
2. प्रमण्डल कार्यालय, सीमा शुल्क (निवारण)—	मोतिहारी
3. प्रमण्डल कार्यालय, सीमा शुल्क (निवारण)—	फारबिसगंज

[सं० II (7) 2–हिन्दी प्रगति/76]

हस्ता०

सहायक समाहर्ता (मुख्यालय)

Office of the Collector of Customs (Preventive), Indo-Nepal Border, Patna

S.O. 1408.—In pursuance of sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the Office of the Collector of Customs (Preventive), Indo-Nepal Border, Patna and its following Divisional Offices, the staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi :—

1. Divisional Office (Customs Preventive)	Muzaffarpur
2. Divisional Office (Customs Preventive)	Motihari
3. Divisional Office (Customs Preventive)	Forbisganj

[F. No. II(7)2-Hindi(Pro.)/76]

Sd/-

Assistant Collector (Hqrs.)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क के समाहर्ता का कार्यालय, पुणे

पुणे, 6 अप्रैल, 1978

का०आ० 1409—केन्द्रीय उत्पादशुल्क नियम 1944 के नियम 173–छ के उपनियम (4) के खंड (ग) द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, समाहर्तालय की दिनांक 28-1-78 की अधिसूचना सं० 4/78 में निम्नलिखित और संशोधन किया जाता है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना में क्रम सं० 8 के पश्चात् निम्नलिखित समाविष्ट किया जाए "(9) बिजली 11 इ"

[अधिसूचना सं० 5/1978/फा० स० V जी एन (30)-46/टीए/78]

जे० एम० वर्मा, समाहर्ता

Office of the Collector of Central Excise & Customs, Pune

Pune, the 6th April, 1978

S.O. 1409.—In exercise of the powers conferred on me by clause (C) of sub-rule (4) of Rule 173-G of Central Excise Rules, 1944, the following further amendment is made in the Collectorate's Notification No. 4/78 dated 28-1-78, namely :—

In the said notification, after serial No. 8 the following may be added

"(9) Electricity 11E"

[Notification No. 5/1978/F. No. VGN(30)-46/TA/78]

J. M. VERMA, Collector

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 26 अप्रैल 1978

बीमा

का०आ० 1410—केन्द्रीय सरकार, साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 16 की उपधारा (1) और (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, साधारण बीमा (पर्यवेक्षी, लिपिकवर्गीय और अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण और पुनरीक्षण) स्कीम, 1974 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात्.—

1. (1) इस स्कीम का नाम साधारण बीमा (पर्यवेक्षी, लिपिकवर्गीय और अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तो का सुव्यवस्थीकरण और पुनरीक्षण) तृतीय संशोधन स्कीम, 1978 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. साधारण बीमा (पर्यवेक्षी, लिपिकवर्गीय और अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तो का सुव्यवस्थीकरण और पुनरीक्षण) स्कीम, 1974 की प्रथम अनुसूची में, "अर्हतः वेतन" से संबन्धित मद 1 में, पैरा (5) में, '27 मई, 1974' अंकों और शब्दों के स्थान पर "1 जनवरी, 1973" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[फा० सं० 65(13) बीमा III/(1)/76]

देस राज अहुजा, अवर सचिव

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 26th April, 1978

INSURANCE

S.O. 1410.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (6) of section 16 of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972), the Central Government hereby makes the following Scheme to amend the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and Other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Scheme, 1974, namely :—

1. (1) This Scheme may be called the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Third Amendment Scheme, 1978.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the First Schedule to the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Scheme, 1974, in item IV relating to "Qualification Pay", in paragraph (5), for the figures, letters and word "27th May, 1974", the figures, letters and word "1st January, 1973" shall be substituted.

[F. No. 65(13)Ins. III/1/76]

D. R. AHUJA, Under Secy.

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 1978

का०आ० 1411.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की तीसरी सूची के फार्म 'क' में दिये गये नोट (च) के उपबन्ध निम्नलिखित बैंकों अर्थात् :—

1. देना बैंक
2. सेंट्रल बैंक आफ इंडिया
3. यूनियन बैंक आफ इंडिया
4. इलाहाबाद बैंक

पर उनके 31 दिसम्बर, 1977 तक के तुलन पत्र के बारे में लागू नहीं होंगे जो कि कथित फार्म के सम्पत्ति और परिसम्पत्ति पक्ष की मद 4 के उप-शीर्ष (2), (3), (4) और (5) में से किसी के सामने के अन्दरवाले खाने में दिखाये गये मूल्य के उस उप-शीर्ष के अन्तर्गत निवेशों के बाजार-मूल्य से बढ़ जाने पर, उस उप-शीर्ष के अन्तर्गत निवेशों के बाजार मूल्य को अलग से कोष्ठकों में दिखाता है ।

[संख्या 15(7)-बी०ओ० III/78]

(Banking Division)

New Delhi, the 27th April, 1978

S.O. 1411.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of Note (f) appended to the Form 'A' in the Third Schedule to the said Act shall not apply to the following banks, viz.,

1. Dena Bank
2. Central Bank of India
3. Union Bank of India
4. Allahabad Bank

in respect of their balance-sheet as at the 31st December 1977, which, when the value shown in the inner column against any of the sub-heads (ii), (iii), (iv) and (v) of item 4 of the Property and Assets side of the said Form exceeds the market value of the investments under that sub-head, shows separately within brackets the market value of the investments under that sub-head.

[No. 15(7)-B.O. III/78]

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 1978

का०आ० 1412.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्द्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 19(2) के उपबन्ध इस अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक युनाइटेड बैंक आफ इंडिया पर उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहां तक उक्त उपबन्ध इस बैंक को स्टेन्डर्ड मोपेड कम्पनी प्राइवेट लि० के 61 प्रतिशत शेयरों को गिरवी के रूप में रखने से रोकते है ।

[सं० 15(6)-बी०ओ०-III/78]

एम० बी० उसगांवकर, अवर सचिव

New Delhi, the 29th April, 1978

S.O. 1412.—In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of section 19(2) of the said Act shall not apply for a period of one year from the date of this notification to the United Bank of India in so far as the said provisions prohibit the bank from holding as pledgee, 61 per cent shares of the Standard Moped Company Pvt. Ltd.

[No. 15(6)-B.O. III/78]

M. B. USGAONKAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 मई, 1978

का०आ० 1413.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 के खण्ड 8 के उपखण्ड (1) के साथ पठित खण्ड 3 के उपखण्ड (क) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्, श्री के० के० पै को 1 अप्रैल, 1978 से आरम्भ होने वाली और 23 अप्रैल, 1978 को समाप्त होने वाली अतिरिक्त अवधि के लिए, सिण्डीकेट बैंक के प्रबन्ध निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त करती है ।

[सं० एफ० 9/4/78-बी०ओ० I (1)]

New Delhi, the 2nd May, 1978

S.O. 1413.—In pursuance of sub-clause (a) of clause 3, read with sub-clause (1) of clause 8, of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby re-appoints Shri K. K. Pai as the Managing Director of the Syndicate Bank for a further period commencing on 1st April, 1978 and ending with 23rd April, 1978.

[No. F. 9/4/78-BO. I(1)]

का०आ० 1414.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 के खण्ड 7 के साथ पठित खण्ड 5 के उपखण्ड (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्, श्री के०के० पै को, जिन्हें 1 अप्रैल, 1978 से सिण्डीकेट बैंक के प्रबन्ध निदेशक के रूप में पुन. नियुक्त किया गया है, उसी तारीख से सिण्डीकेट बैंक के निदेशक-बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है ।

[सं० एफ० 9/4/78-बी० ओ० 1(2)]

बलदेव सिंह, संयुक्त सचिव

S.O. 1414.—In pursuance of sub-clause (1) of clause 5, read with clause 7, of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints Shri K. K. Pai, who has been re-appointed as Managing Director of Syndicate Bank with effect from 1st April, 1978 to be the Chairman of the Board of Directors of the Syndicate Bank with effect from the same date.

[No. F. 9/4/78-BO. I(2)]

BALDEV SINGH, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 4 मई, 1978

का०आ० 1415.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 31 तथा बैंककारी विनियमन (सहकारी समितियां) नियम, 1966 के नियम 10 के उपबन्ध सत्यमंगलम कोआपरेटिव अर्बन बैंक लि०, सत्यमंगलम पर उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहां तक उनका सम्बन्ध 30 जून, 1977 को समाप्त हुए वर्ष के लिये इसके तुलन पत्र, लाभ और हानि खाते तथा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के समाचार पत्र के प्रकाशित होने से है ।

[संख्या एफ० 8-2/78-ए०सी०]

एम०पी० वर्मा, अवर सचिव

New Delhi, the 4th May, 1978

S.O. 1415.—In exercise of the powers conferred by the section 53 read with section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of section 31 of the said Act and Rule 10 of the Banking Regulation (Co-operative Societies) Rules, 1966 shall not apply to the Satyamangalam Co-operative Urban Bank Ltd., Satyamangalam in so far as they relate to the publication of its balance sheet, profit and loss account for the year ended the 30th June, 1977 together with the auditor's report in a newspaper.

[No. F. 8-2/78-AC]

M. P. VARMA, Under Secy.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 9 मार्च, 1978

आय कर

का०आ० 1416 —केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड, आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 13) की धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपनी अधिसूचना सं० 1 (फा० सं० 55/235/63-आई० टी०) तारीख 18 मई, 1964 से उपाबद्ध अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्—

क्रम सं० 3(घ) (ग) की प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्—

क्रम सं०	व्यक्ति	आयकर अधिकारी	सहायक आयुक्त निरीक्षण	सहायक आयकर आयुक्त अपील	आयकर आयुक्त
1	2	3	4	5	6
	ऐसे सभी व्यक्ति जो निवासी नहीं है जिनका भारत में कोई कार्यालय नहीं है और जिसे ऐसे व्यक्तियों से या उसके माध्यम से कोई आय होती है या व्यापार संबन्ध है जिनका मामला कम्पनी जिला-5 कलकत्ता को सौंपा गया है ।	सभी आय-कर अधिकारी कम्पनी जिला—5 कलकत्ता ।	सहायक आयकर आयुक्त, निरीक्षण, जिसे कम्पनी जिला-5 कलकत्ता की बाबत सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण के कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किया गया है ।	सहायक आयकर आयुक्त, अपील, जिसे स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट आयकर अधिकारी/आयकर अधिकारियों के विनिश्चय के विरुद्ध अपील सुनने की शक्ति प्रदान की गई है ।	आय-कर आयुक्त पश्चिमी बंगाल-5 कलकत्ता

ये उपरोक्त प्राधिकारी ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गों अथवा मामलों या मामलों के वर्गों के अतिरिक्त, जो इन प्राधिकारियों को विशेष रूप से समनुदिष्ट किए गए हों और भविष्य में उन्हें समनुदिष्ट किए जाएं, स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की बाबत कृत्यों का पालन करेंगे ।

यह अधिसूचना 9-3-1978 से प्रभावी होगी ।

[सं० 2212/फा० सं० 188/2/78-आई टी (ए 1)]

CENTRAL BOARD OF DIRECT TEXES

New Delhi, the 9th March, 1978

(INCOME-TAX)

S.O. 1416.—In exercise of the powers conferred by section 126 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments in the Schedule annexed to its Notification No. 1 (F. No. 55/233/63-II) dated 18th May, 1964. After the entry at Sl. No. 3(d)(c) the following shall be added.

Sl. No.	Persons	I.T.O.	I.A.C.	A.A.C.	C.I.T.
1	2	3	4	5	6
3(e)	All persons who are Non-residents having no Office in India and who are in receipt of any income from or through or have business connection with any person whose case is assigned to the Companies Dist.-V, Calcutta.	All I.T.Os, Companies Dist.-V, Calcutta.	Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax who has been appointed to perform the functions of an Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax in respect of Companies Dist.-V Calcutta.	Appellate Assistant Commissioner of Income-Tax who has been invested with powers to hear appeals against the decision of the I.T.O./ I.T.Os referred to in Col. 3.	Commissioner of Income-Tax, West Bengal-V, Calcutta.

These above authorities will exercise the functions in respect of persons specified in the 2nd Col. over and above to persons or classes of persons or cases or classes of cases that have been specifically assigned to these authorities and may be assigned to them in future.

This notification will have effect from 9-3-1978.

[No. 2212/F. No. 188/2/78-IT(AI)

नई दिल्ली, 29 मार्च, 1978

आय-कर

का०आ० 1417.—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर यथा संशोधित अपनी अधिसूचना सं० 1 (फा० सं० 55/233/63-आ०क०) तारीख 18-5-1964 से उपाबद्ध अनुसूची में निम्नलिखित परिवर्धन करती है ।

उक्त अनुसूची में क्रम सं० 85 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :—

अनुसूची

1	2	3	4	5	6
(I)	वे व्यक्ति जो भारत के निवासी नहीं हैं और जिन पर भारत में पहले कहीं भी निर्धारण नहीं किया गया है या निर्धारणीय नहीं है और जो आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 230 की उपधारा (1) के अधीन प्रमाणपत्र के लिए आयकर अधिकारी, विदेश अनुभाग, सूरत को आवेदन करते हैं ।	आयकर अधिकारी विदेश अनुभाग सूरत	सहायक आयकर आयुक्त सूरत रेंज II, सूरत	सहायक आयकर आयुक्त (अपील) ख रेंज सूरत	आयकर आयुक्त गुजरात-II
(II)	यदि आवेदन आयकर अधिकारी, विदेश अनुभाग, बड़ौदा को किया जाए ।	आयकर अधिकारी, विदेश अनुभाग, बड़ौदा	सहायक आयकर आयुक्त बड़ौदा रेंज II, बड़ौदा	सहायक आयकर आयुक्त (अपील) बड़ौदा रेंज बड़ौदा	आयकर आयुक्त गुजरात-IV
(III)	यदि आवेदन आयकर अधिकारी, विदेश अनुभाग, आनन्द को किया गया है ।	आयकर अधिकारी, विदेश अनुभाग, आनन्द	सहायक आयकर आयुक्त अहमदाबाद रेंज IV, अहमदाबाद	सहायक आयकर आयुक्त (अपील) अहमदाबाद	आयकर आयुक्त गुजरात-III

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1978 से प्रभावी होगी ।

[सं० 2231/फा० सं० 188/3/78-आ०क० (ए-1)]

एम० शास्त्री, अवर सचिव

New Delhi, the 29th March, 1978

(INCOME TAX)

S.O. 1417.—In exercise of the powers conferred by Section 126 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following additions to the Schedule annexed to its notification No. 1 (F. No. 55/233/63-II) dated 18-5-1964, as amended from time to time.

After Sl. No. 85 in the said Schedule the following shall be added.

SCHEDULE

1	2	3	4	5	6
(i)	Persons not domiciled in India and not previously assessed or assessable anywhere in India who apply for a certificate under sub-section (1) of Section 230 of the Income-tax Act, 1961, to The Income-tax Officer, Foreign Section, Surat.	I.T.O., F.S., Surat	I.A.C., S.R. II, Surat	A.A.C., B-Range, Surat.	C.I.T., Gujarat-II.
(ii)	If the application is made to the Income-tax Officer, Foreign Sec., Baroda.	I.T.O., F.S., Baroda	I.A.C., B.R. II. Baroda.	A.A.C., B-Range, Baroda.	C.I.T., Gujarat-IV.
(iii)	If the application is made to the Income-tax Officer, Foreign Sec., Anand.	I.T.O., F.S., Anand	I.A.C., A.R. IV, Ahmedabad.	A.A.C., A.R. IV, Ahmedabad.	C.I.T., Gujarat-III.

This notification shall take effect from 1st April, 1978

[No. 2231 F. No. 188/3/78-IT (AI)]

M. SHASTRI, Under Secy.

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात का कार्यालय

आदेश

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 1978

का० आ० 1418.—सर्वश्री हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि०, 765-सी० पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता को 19,27,662-रुपए (उन्नीस लाख सताइस हजार छह सौ बासठ रुपए मात्र) के लिए एक आयात लाइसेंस सं० आई-सी जी/2032616/आर/एसडब्ल्यू/63/एच/45-46/सी जी०-2 एल एस, दिनांक 2 मई, 1977 प्रदान किया गया था। उन्होंने उक्त आयात लाइसेंस (दोनों प्रतियां—सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति) की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल लाइसेंस की दोनों प्रतियां खो गई/अस्थानस्थ हो गई हैं। आगे यह भी बताया गया कि मूल आयात लाइसेंस कोचीन पत्तन पर सीमा शुल्क प्राधिकारियों के पास पंजीकृत नहीं किया गया था और आगे यह भी बताया गया है कि उक्त लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति के मदे 10% का अग्रिम भुगतान अथवा आस्ट्रेलिया डालर 18,406.80 के बराबर आदेश दिए गए मूल्य पार्टी को पहले से ही प्रेषित कर दिया गया है।

2. इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने नोटरी, कलकत्ता से एक प्रमाण-पत्र के साथ एकल पथ-पत्र दाखिल किया है। तदनुसार मैं संतुष्ट हूं कि उक्त लाइसेंस की मूल सीमा शुल्क और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई है। अतः यथा संशोधित आयात व्यापार (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-55 की उप-धारा 9 (सी सी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि० कलकत्ता के नाम में जारी किए गए लाइसेंस सं० आई/सी जी/2032616, दिनांक 2 मई, 1977 की मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति को रद्द किया जाता है।

3. उक्त लाइसेंस की सीमा शुल्क/मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि प्रति लाइसेंस धारी को अलग से जारी की जा रही है।

[सख्या सी जी-2/आई डी (3)/77-78/37]

टी० टी० ला, उप-मुख्य नियंत्रक

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

(Office of the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi)

ORDER

New Delhi, the 12th April, 1978

S.O. 1418.—M/s. Hindustan Paper Corporation Ltd., 75-C, Park Street, Calcutta were granted an Import Licence No. 1/CG/2032616/R/SW/63/H/45-46/CG-II/LS dated the 2nd May, 1977 for Rs. 19,27,662 (Rupees nineteen lakhs twenty seven thousand six hundred and sixty two only). They have applied for the issue of a duplicate copy of the said import licence (both copies—Customs Purposes and Exchange Control Purposes) on the ground that both the copies of the original licence has been lost/misplaced. It is further stated that the original import licence was not registered with the Customs authorities at Cochin Port and have further stated that against the exchange control copy of said import licence, an advance payment of 10 per cent or order value amounting to Australian Dollar 18,406.80 has already been remitted to the party.

2. In support of this contention, the applicant has filed an affidavit alonwgith a certificate from Notary, Calcutta. I am accordingly satsiffied that the original Customs and Exchange Control Copies of the said licence have been lost. Therefore, in exercise of the powers conferred under Sub-clause 9(cc) of the Imports Trade (Control) Order, 1955 dated 7-12-55 as amended, the said original Customs Purposes and Exchange Control Purposes Copies of licence No. I/CG/2032616 dated 2nd May, 1977 issued to M/s. Hindustan Paper Corporation Ltd., Calcutta is herewith cancelled.

3. A duplicate Customs purposes/Exchange Control Purposes copies of the said licence are being issued separately to the licensee.

[No. CG-II/ID(3)/77-78/37]

T. T. LA, Dy. Chief Controller

आदेश

नई दिल्ली, 3 मई, 1978

का०आ० 1419—सर्वश्री मोदी रबड़ लि०, मोदीनगर, जि० गाजियाबाद को प० जर्मनी से ब्यूटल ट्यूब्स के आयात के लिए 6,989 रुपए के लिए सीमा-शुल्क निकासी परमिट (मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति के बिना) सं० पी/जे/3055352 दिनांक 26-8-77 प्रदान किया गया था।

2. पार्टी ने ऊपर उल्लिखित सीमा शुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमा शुल्क निकासी परमिट उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। लाइसेंसधारी ने आगे यह भी बताया है कि सीमा शुल्क निकासी परमिट बिल्कुल उपयोग में नहीं लाया गया है और भारत में किसी भी पत्तन पर पंजीकृत नहीं कराया गया है।

3. अपने तर्क के समर्थन में, आवेदकों ने एक शपथ-पत्र दाखिल किया है। अधोहस्ताक्षरी सन्तुष्ट है कि मूल सीमा शुल्क निकासी परमिट सं० पी/जे/3055352 दिनांक 26-8-77 खो गया है तथा निदेश देता है कि आवेदक को सीमा-शुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति जारी की जानी चाहिए। मूल सीमा शुल्क निकासी परमिट एतद् द्वारा रद्द किया जाता है।

4. लाइसेंस की सीमा शुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति अलग से जारी की जा रही है।

[म० रबड़/4(4)77-78 आरएम-II/98]

जी० एस० ग्रेवाले, उप-मुख्य नियंत्रक

कृते मुख्य नियंत्रक

ORDER

New Delhi, the 3rd May, 1978

S.O. 1419.—M/s. Modi Rubber Ltd., Modinagar, Distt. Ghaziabad were granted CCP (without exchange control copy) No. P/J/3055352 dated 26-8-77 under West Germany for Rs. 6,989 only for import of Butyl Tubes.

2. The firm have requested for issue of duplicate Customs Clearance Purposes copy of the above mentioned CCP on the ground that the original CCP has not been received by them. It has been further reported by the licensee that the CCP has not been utilized at all and has not been registered with any port in India.

3. In support of their contention, the applicants have filed an affidavit. The undersigned is satisfied that the original CCP No. P/J/3055352 dated 26-8-77 has been lost and directs that a duplicate CCP should be issued to the applicants. The original CCP is hereby cancelled.

4. The Duplicate CCP of the licence is being issued separately.

[No. Rubber/4(4)/77-78/RM-II/98]

G. S. GREWAL, Dy. Chief Controller
for Chief Controller

आदेश

नई दिल्ली, 13 मई, 1978

का० आ० 1420—भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए फल उत्पादों को निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन करने के लिए कतिपय प्रस्ताव, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उप-नियम (2) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के वाणिज्य मन्त्रालय के आदेश संख्या का० आ० 1267, तारीख 30 अप्रैल, 1977 के अधीन भारत के राजपत्र भाग-2, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 30 अप्रैल 1977 प्रकाशित किए गए थे ;

और उन व्यक्तियों से जिनका उससे प्रभावित होना संभाव्यतः था 15 जून, 1977 तक आक्षेप तथा सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 2 मई, 1977 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और उक्त प्रारूप पर जनता से प्राप्त आक्षेपों तथा सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है ;

अतः, अब, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार की निर्यात निरीक्षण परिषद से परामर्श करने के पश्चात्, यह राय है कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है, और वह एतद्द्वारा—

(1) अधिसूचित करती है कि फल उत्पाद निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण निरीक्षण के अधीन होंगे;

(2) फल उत्पादों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1978 के अनुसार क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार को, निरीक्षण के ऐसे प्रकार के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जो निर्यात से पूर्व ऐसे फलों के उत्पादों पर लागू होगा :

(3) (i) क्रेता तथा विक्रेता के बीच करार पाए गए विनिर्देशों को मान्यता देती है कि वह आयात करने वाले देश की खाद्य विधियों के अनुरूप हों तथा निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अभिकरण द्वारा सम्यकतः अनुमोदित किए गए हों ;

(ii) खंड (i) में निर्दिष्ट विनिर्देशों की अनुपस्थिति में, समय समय पर यथा संशोधित फल उत्पाद आदेश, 1955 में निहित विनिर्देशों को मान्यता देती है :

(4) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान उक्त फल के उत्पादों के निर्यात को तब तक प्रतिषेद्ध करती है जब तक कि निर्यात के लिए आशयित इसके प्रत्येक परेषण के साथ उप-पैरा (3) के खंड (i) निर्दिष्ट अभिकरण द्वारा जारी किया गया निर्यात योग्यता प्रमाण-पत्र संलग्न न हो।

2. इस आदेश की कोई भी बात भावी क्रेताओं को भूमि, समुद्र या वायुमार्ग द्वारा किए गए फल उत्पादों के नमूनों निर्यात पर लागू नहीं होगी परन्तु यह तब जब कि ऐसे नमूनों का मूल्य पोतपर्यन्त निःशुल्क मूल्य के एक सौ रुपये से अधिक नहीं है ।

3. इस आदेश में "फल उत्पादों" से अभिप्रेत है,—

1. कृत्रिम पेय, सिरप और शरबत ;

2. सिरका चाहे तैयार किया हुआ हो या कृत्रिम ;

3. अचार ;

4. निर्जलित फल तथा सब्जियां;

5. स्क्वैश, क्रश, कार्डियल, जौ का पानी, बैरल रस तथा तुरन्त उपयोग योग्य फलों के रस या फलों के गूदे वाले अन्य पेय;

6. जैम, जैली तथा मुरब्बे ;

7. टमाटर उत्पाद, चटनी तथा सॉस ;

8. परिरक्षित, पैक किए हुए और किस्टल किए हुए फल तथा छिलके ;

9. चटनियां ;

10. डिब्बे तथा बोतल में बंद फल, रस तथा गूदा ;

11. जिब्बे तथा बोतल में बंद सब्जियां ;

12. प्रशीतित फल तथा सब्जियां—

13 फलों के रस तथा गूदे वाला वातित जल ;

14. फल अम्ल फलैक्सः तथा

15. फल तथा सब्जियों से संबंधित अविनिर्दिष्ट कोई अन्य वस्तुएं;

यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

[सं० 6/2/77-नि० नि० तथा नि० ऊ०]

ORDER

New Delhi, the 13th May, 1978

S.O. 1420.—Whereas for the development of the export trade of India, certain proposals for subjecting fruit products to Quality Control and Inspection prior to export were published as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964 in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (ii) dated the 30th April, 1977 under the order of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 1267 dated the 30th April, 1977 ;

And whereas objections and suggestions were invited till the 15th June, 1977 from all persons likely to be affected thereby;

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on the 2nd May, 1977;

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft have been considered by the central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) the Central Government after consulting the Export Inspection Council being of opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of the export trade of India, hereby—

(1) Notifies that fruit products shall be subject to quality Control and Inspection prior to export;

(2) Specifies the types of Quality Control and Inspection in accordance with the Export of Fruit Products (Quality Control and Inspection) Rules, 1978 as the type of inspection, which shall be applied to such fruit products prior to export;

(3) recognises—

(i) the specifications agreed to between the buyer and the seller provided these conform to the Food laws of the importing country and are duly approved by the agency recognised the Central Government under article 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) ;

(ii) in the absence of the specification referred to in clause (1) the specification prescribed in the Fruit Products Order, 1955, as amended, from time to time;

(4) Prohibits the export in the course of international trade of the said fruit products unless each and every consignment of the same meant for export is

accompanied by a certificate of export worthiness issued by the agency referred to in clause (i) of sub-paragraph (3).

2. Nothing in this order shall apply to the export of samples of the fruit products to the prospective buyers by land, sea or air provided the value of such samples does not exceed in f.o.b. value of rupees one hundred.

3. In this order 'Fruit products' means —

1. Synthetic beverages, syrups and sharbats ;
2. Vinegar, whether brewed or synthetic ;
3. Pickles;
4. Dehydrated fruits and vegetables ;
5. Squashes, crushes, cordial, barely water, barreled juice and ready-to-serve beverage, fruit nector or any other beverages containing fruit juices or fruit pulp;
6. Jams, Jellies and marmalades;
7. Tomato products, katchup and sauce;
8. Preserved, candied and crystalised fruits and peels;
9. Chatneys;
10. Canned and bottled fruits, juices and pulp;
11. Canned and bottled vegetable ;
12. Frozen fruits and vegetables;
13. Aerated waters containing fruit juice and plup,
14. Fruit cereal flakes ; and
15. Any other unspecified items relating to fruits or vegetables.

4. This order shall come into force on the date of its publication in the official gazette.

[No. 6/2/77-EI&EP]

का० आ० 1421.—केन्द्रीय सरकार निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम फल उत्पादों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1978 है ।

(2). ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(i) 'अधिनियम' से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है ;

(ii) 'अभिकरण' से कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग) में फल तथा सब्जी के परिरक्षण निदेशक का कार्यालय अभिप्रेत है जो अधिनियम की धारा 7 के अधीन अभिकरण के रूप में मान्यता प्राप्त है ;

(iii) 'फल उत्पाद' से अभिप्रेत है—

1. कृत्रिम पेय, सिरप और शरबत ;
2. सिरका चाहे तैयार किया हुआ हो या कृत्रिम ;
3. अचार ;
4. निर्जलित फल तथा सब्जियां ;
5. स्क्वैश, क्रश, कार्डियल, जौ का पानी, बैरल रस तथा तुरन्त उपयोग योग्य फलों के रस या फलों के गूदे वाले अन्य पेय ;
6. जैम, जैली तथा मुरब्बे ;
7. टमाटर उत्पाद चटनी तथा सॉस ;
8. परिरक्षित, पैक किए हुए और क्रिस्टल किए हुए फल तथा छिलके ;
9. चटनिया ;
10. डिब्बे तथा बोतल में बंद फल, रस तथा गूदा ;
11. डिब्बे तथा बोतल में बंद सब्जियां ;
12. प्रशीतित फल तथा सब्जियां ;
13. फलों के रस तथा गूदों वाला वातित जल ;
14. फल अनफलैक्स तथा
15. फल तथा सब्जियो से सम्बन्धित अविनिर्दिष्ट कोई अन्य वस्तुए

(iv) 'अनुज्ञप्ति धारक' से ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है जिसे फल उत्पाद आदेश, 1955 के अधीन अनुज्ञप्ति दी गई है ।

3. निरीक्षण का आधार .—फल उत्पादों का निरीक्षण यह देखने की दृष्टि से किया जाएगा कि वह अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्य मानक विनिर्देशों के अनुरूप है ।

4. निरीक्षण की प्रक्रिया .—(1) निर्यात के लिए बनाए गए फल उत्पाद केवल अनुज्ञाप्त धारक द्वारा प्रसंस्कृत तथा पैक किए जाएंगे ।

(2) फल उत्पादों के निर्यात करने का इच्छुक अनुज्ञप्ति धारक, अभिकरण के निकटतम कार्यालय को लिखित रूप में सूचना देगा ताकि वह उस का निरीक्षण कर सके तथा नियम 3 के अनुसार विश्लेषण के लिए नमूने ले सके ।

(3) अभिकरण के कार्यालयों के पते निम्नलिखित हैं :—

(i) फल तथा सब्जी परिरक्षण उप-निदेशक का कार्यालय, जामनगर हाऊस, ब्लाक नं० 11, नई दिल्ली ।

(ii) फल तथा सब्जी परिरक्षण, उप-निदेशक का कार्यालय, तीसरी मंजिल, न्यू मेरीन लाईंस, मुम्बई ।

(iii) फल तथा सब्जी परिरक्षण, उप-निदेशक का कार्यालय, 8, एस पले डे (पूर्व) कलकत्ता-69.

(iv) फल तथा सब्जी परिरक्षण, उप-निदेशक का कार्यालय, शास्त्री भवन, चौथी मंजिल, हैडोस रोड, मद्रास ।

(4) उप-नियम (2) के अधीन प्रत्येक सूचना —

(क) अभिकरण के किसी भी कार्यालय के मुख्यालय पर, विश्लेषण के लिए, नमूने लिए जाने से कम से कम तीन दिन पूर्व दी जाएगी ।

(ख) उन स्थानों पर जो अभिकरण के किसी भी कार्यालय के मुख्यालय पर स्थित नहीं है, विश्लेषण के लिए नमूने लिये जाने से कम से कम दस दिन पूर्व दी जाएगी ।

(5) उप-नियम (4) में निर्दिष्ट सूचना के प्राप्त होने पर अभिकरण फल उत्पादों के परेषणो का निरीक्षण यह जांच करने की दृष्टि से करेगा कि वे नियम 3 में निर्दिष्ट मान्य विनिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुरूप है।

(6) यदि अभिकरण का यह निष्कर्ष हो कि परेषण विहित विनिर्देशो के अनुरूप है तो वह उप-नियम (4) के अधीन निरीक्षण के लिए दिए गए परेषणों के लिए निरीक्षण प्रमाण-पत्र जारी करेगा :

परन्तु यदि अभिकरण का इस प्रकार समाधान नहीं होता है तो वह निरीक्षण प्रमाण-पत्र देने से इंकार कर देगा तथा निरीक्षण के लिए सूचना प्राप्त होने की तारीख से दस दिन के भीतर अनुज्ञप्ति धारक को उसके कारणों सहित लिखित रूप में उस तथ्य की सूचना देगा ।

5. निरीक्षण के स्थान :—(1) इन नियमों के प्रयोजनार्थों के लिए निरीक्षण अनुज्ञप्ति धारक के प्राधिकृत परिसर पर या अनुज्ञप्ति धारक के अनुमोदित भंडारगृह या गोदाम में किया जाएगा ।

(2) उत्पाद की नमूना जांच निर्यात से पूर्व किसी भी प्रक्रम पर की जा सकती है ।

6. परीक्षण या जांच नमूने की पुनः परीक्षा :—यदि अनुज्ञप्ति धारक का अभिकरण द्वारा की गई परीक्षा के परिणामों से समाधान नहीं होता है तो वह अभिकरण से परेषण की पुनः परीक्षण के प्रबंध के लिए लिखित में निवेदन करने का हकदार होगा तथा उसके पश्चात एक और परीक्षण नमूना या जांच नमूना लिया जाएगा और परीक्षण किया जाएगा ।

(2) उप-नियम (1) के अधीन विश्लेषण का परिणाम पहले वाले नमूनों के परिणामों के साथ विनियस्त किया जाएगा और परेषण की क्वालिटी निश्चित करने के लिए औसत परिणाम निकाला जाएगा ।

7. अपील :—(1) नियम 4 के उप-नियम (6) के अधीन अभिकरण द्वारा प्रमाण-पत्र देने से इंकार किए जाने से व्यथित कोई व्यक्ति, उसके द्वारा ऐसे इंकार की सूचना प्राप्त होने के दस दिन के भीतर इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा उस प्रयोजन के लिए नियुक्त विशेषज्ञों के पैनल को, जिसमें कम से कम तीन और अधिक से अधिक सात व्यक्ति होंगे, अपील करेगा ।

(2) विशेषज्ञों के पैनल की कुल सदस्य संख्या के कम से कम दो-तिहाई अशासकीय व्यक्ति सदस्य होंगे ।

(3) पैनल की गणपूर्ति तीन की होगी ।

(4) अपील, उसकी प्राप्ति से पन्द्रह दिन के भीतर निपटाई जाएगी।

[सं० 6/2/77-नि० नि० तथा नि० उ०]

S.O. 1421.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Export of Fruit Products (Quality Control and Inspection) Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires (i) 'Act' means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) ;

(ii) 'Agency' means the office of the Director of Fruit and Vegetables Preservation in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Deptt. of Food) recognised as Agency under section 7 of the Act.

(iii) 'Fruit Products' means —

1. Synthetic beverages, syrups and sharbats ;
2. Vinegar, whether brewed or synthetic ;
3. Pickles ;
4. Dehydrated fruits and vegetables;
5. Squashes, crushes, cordial, barley water, barreled juice and ready-to-serve beverage, fruit nector or any other beverages containing fruit juices or fruit pulp ;
6. Jams, jellies and marmalades;
7. Tomato products, ketchup and sauce;
8. Preserved, candied and crystallised fruits and peels;
9. Chatneys ;
10. Canned and bottled fruits, juices and pulp;
11. Canned and bottled vegetables;
12. Frozen fruits and Vegetables ;
13. Aerated waters containing fruit juice and pulp ;
14. Fruits cereal flakes ; and
15. Any other unspecified items relating to fruits or vegetables.

(iv) 'Licence Holder' means the person or body of persons who have been granted licence under the Fruit Products Order, 1955 ;

3. Basis of Inspection.—Inspection of the Fruit Products shall be carried out with a view to seeing that the same conform to the standard specifications recognised by the Central Government under Section 6 of the Act.

4. Procedure of Inspection.—(1) Fruit Products meant for export shall be processed and packed only by a licence holder;

(2) A licence holder intending to export Fruit Products shall give intimation in writing to the nearest office of the agency to enable it to inspect the same and draw samples for analysis in accordance with rule 3.

(3) The addresses of the offices of the Agency are as follows :

(i) office of the Deputy Director, Fruit & Vegetable Preservation, Jamnagar House, Block No. 11, New Delhi.

(ii) Office of the Deputy Director, Fruit & Vegetable Preservation, 3rd Floor, New Marine Lines, Bombay.

(iii) Office of the Deputy Director, Fruit & Vegetable Preservation, 8, Esplanade (East), Calcutta-69.

(iv) Office of the Deputy Director, Fruit & Vegetable Preservation, Shastri Bhawan, 4th Floor, Haddows Road, Madras.

(4) Every intimation under sub-rules (2) shall be given—

(a) not less than 3 days before the samples are drawn for analysis at the headquarters of any office of the agency;

(b) not less than 10 days before the samples are drawn for analysis at other places which are not situated at the headquarters of any office of the agency.

(5) On receipt of the intimation referred to in sub-rule (4) the agency shall inspect consignments of fruit products with a view to check up that the same complies with the requirements of the recognised specifications referred to in rule 3.

(6) The agency on finding that the consignment conforms to the prescribed specifications, shall arrange to issue the inspection certificate for the consignments tendered for inspection under sub-rule (4) :

Provided that if the agency is not so satisfied it shall refuse to issue the inspection certificate and convey the fact in writing not later than 10 days from the date of receipt of intimation for inspection to the licence holder giving the reasons therefor.

5. Places of Inspection.—(1) Inspection for the purposes of these rules shall be carried out at the authorised premises of the licence holder or an approved store or godown of the licence holder; (2) Check sampling of the product may be done at any point before export.

6. Re-examination of the test of check sample—If the licence holder is not satisfied with the results of examination by the agency, he shall be entitled to request the agency in writing to arrange for re-examination of the consignment and one more test sample or check sample shall thereafter be drawn and tested.

(2) The result of analysis under sub-rule (1) shall be arranged with those of the previous samples and the average result shall be taken for determining the quality of the consignment.

7. Appeal—(1) Any person aggrieved by the refusal of the agency to issue an inspection certificate under sub-rule (6) of rule 4 may within ten days of the receipt of the communication of such refusal by him prefer an appeal to a Panel of Experts consisting of not less than three but not more than seven persons appointed for the purpose by the Central Government.

(2) At least two thirds of the total membership of the panel of experts shall consist of non-officials.

(3) The quorum for the panel shall be three.

(4) The appeal shall be disposed off within 15 days of its receipt.

[No. 6/2/77-EI&EP]

का० आ० 1422—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग) में फल तथा सब्जी परिरक्षण निदेशक के कार्यालय को, निर्यात से पूर्व फल उत्पादकों के क्वालिटी नियंत्रण तथा निरीक्षण के लिए अभिकरण के रूप में मान्यता देती है ।

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए 'फल उत्पाद' से अभिप्रेत है :—

1. कृत्रिम पेय, सिरप और शरबत ;
2. सिरका चाहे तैयार किया हुआ हो या कृत्रिम ;
3. अचार ;
4. निर्जलित फल तथा सब्जियां ;
5. स्क्वैश, क्रश, कार्डियस, जौ का पानी, बैरल रस तथा तुरन्त उपयोग योग्य फलों के रस या फलों के गूदे वाले अन्य पेय ;
6. जैम, जैली तथा मुरब्बे ;
7. टमाटर उत्पाद चटनी तथा सॉस ;
8. परिरक्षित, पैक किए हुए और क्रिस्टल किए हुए फल तथा छिलके ;
9. चटनियां ;
10. डिब्बे तथा बोतल में बंद फल, रस तथा गूदा ;
11. डिब्बे तथा बोतल में बंद सब्जियां ;
12. प्रशीतित फल तथा सब्जियां ;
13. फलों के रस गूदे वाला वातित जल ;
14. फल अन्न फलैक्स तथा ;
15. फल तथा सब्जियों के सम्बन्धित अविनिर्दिष्ट कोई अन्य वस्तुएं ।

[सं० 6/2/77-नि० सि० तथा नि० उ०]

सी० बी० कुकरेती, संयुक्त निदेशक

S.O. 1422.—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby recognises the office of the Director of Fruit and Vegetable Preservation in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Food) as the Agency for Quality Control and Inspection of Fruit Products prior to export.

Explanation :—For the purpose of this notification—'Fruit products' means—

1. Synthetic beverages, syrups and sharbats ;
2. Vinegar, whether brewed or synthetic ;
3. Pickles ;
4. Dehydrated fruits and vegetables ;
5. Squashes, crushes, cordial, barly water, barreled juice and ready-to-serve beverage, fruit nector or any other beverages containing fruit juice or fruit pulp;
6. Jams, Jellies and marmalades ;
7. Tomato products, ketchup and sauce;
8. Preserved, candied and crystallised fruits and peels ;
9. Chatneys ;
10. Canned and Bottled Fruits, Juice and pulp ;
11. Canned and bottled vegetables ;
12. Frozen fruits and vegetables ;
13. Aerated water containing fruit juice and pulp ;
14. Fruit cereal flakes ; and
15. Any other unspecified items relating to fruits or vegetables.

[No. 6/2/77-EI&EP]

C. B. KUKRETI, Jt. Director

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 1978

का० आ० 1423—भारत सरकार के अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में प्रदर्शित किया गया है और पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाइन (प्रयोक्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अंतर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य के मेहसाना तेल क्षेत्र में उक्त परिशिष्ट भूमि में विद्यान स्थल म० एन० के० ए० जेड० से डब्ल्यू० एच० आई-एन०के-25 तक पैट्रोलियम के लिए भूमि उपयोग के अधिकार प्राप्त किए गए हैं ।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपर्युक्त नियम के खण्ड 7 के उपखण्ड (1) की धारा (1) में निर्दिष्ट कार्य दिनांक 31-12-76 से समाप्त कर दिया गया है ।

अतः, अब, पैट्रोलियम पाइप लाइन के नियम (प्रयोक्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) नियम, 1963 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त तिथि को कार्य की समाप्ति तिथि अधिसूचित करते है ।

अनुसूची

एन० के० ए० जेड० से डब्ल्यू० एच० आई० एन० के०-25 तक पाइप लाइन कार्य की समाप्ति

मंत्रालय का नाम	गांव	का० आ०सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक	तेलावी	181	21-1-78	31-12-76

[सं० 12016/3/78-प्रो०-I]

MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS & FERTILIZER

(Deptt. of Petroleum)

New Delhi, the 28th April, 1978.

S.O. 1423.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub-section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from d.s. NKAZ to WHI-NK-25 in Mehsana oil field in Gujarat State.

And whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub-section (1) of section 7 of the said Act on 31-12-76.

Now, therefore, under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

Termination of operation of pipeline from D.S. NKAZ to WHINK-25.

Name of Ministry	Villages	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Petroleum, Chemicals & Fertilizer	Telavi	181	21-1-78	31-12-76

[No. 12016/3/78-Prod-I]

का० आ० 1424.—भारत सरकार के अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में प्रदर्शित किया गया है और पैट्रोलियम और खनिज पाईप लाइन (प्रयोक्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अंतर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य के कलोल तेल क्षेत्र में उक्त परिशिष्ट भूमि में वेधान स्थल सं० के० ओ० डी-17 से जी०जी० एस-2 तक पैट्रोलियम के लिए भूमि उपयोग के अधिकार प्राप्त किए गए हैं।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपर्युक्त नियम के खण्ड 7 के उपखंड (1) की धारा (1) में निर्दिष्ट कार्य दिनांक 3-1-77 से समाप्त कर दिया गया है।

अतः, अब, पैट्रोलियम पाइप लाइन के नियम (प्रयोक्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) नियम, 1963 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्ति की तिथि अधिसूचित करते हैं।

अनुसूची

के० ओ० डी-17 से जी० जी० एस-2 तक पाइप लाईन कार्य की समाप्ति

मंत्रालय का नाम	गांव	का०आ० सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक	सईज	435	18-2-78	3-1-77

[सं० 12016/3/78-प्रो० II]

S.O. 1424.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipelines Acquisition of Right of User in Land Act, 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from d.r. KOD-17 to GGS II in Kalol oil field in Gujarat State.

And whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub-section (1) of sub-section 7 of the said Act on 3-1-77.

Now, therefore, under Rule 4 of the Petroleum Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Rules 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

Termination of operation of pipeline from D.S. KOD-17 to GGS II.

Name of Ministry	Villages	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Petroleum, Chemicals & Fertilizer	Salj	435	18-2-78	3-1-77

[No. 12016/3/78-Prod-II]

का०आ० 1425.—भारत सरकार के अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में प्रदर्शित किया गया है और पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाइन (प्रयोक्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) अधिनियम, 1962 के खंड 6 के उपखंड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य के कलोल तेल क्षेत्र में उक्त परिशिष्ट भूमि में वेधान स्थल सं० के०एच० जेड० (के-187) से जी०जी०एस०-5 तक पैट्रोलियम के लिए भूमि उपयोग के अधिकार प्राप्त किए गए हैं।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपर्युक्त नियम के खंड 7 के उप-खंड (1) की धारा (1) में निर्दिष्ट कार्य दिनांक 24-3-77 से समाप्त कर दिया गया है।

अतः, अब, पैट्रोलियम पाइप लाइन के नियम (प्रयोक्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) नियम, 1963 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्ति तिथि अधिसूचित करते हैं।

अनुसूची

के०एच०जेड० (के०-187) से जी०जी०एस०-5 तक पाइप लाइन कार्य की समाप्ति

मंत्रालय का नाम	गांव	का०आ० सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक	ओला और ईसन्ड	434	18-2-78	24-3-77

[सं० 12016/3/78-प्रो०-III]

S.O. 1425.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub-section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 the right of user has been acquired the land specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from d.s. KHZ (K-187) to GGS-5 in Kalol oil field in Gujarat State.

And whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub section (1) of section 7 of the said Act on 24-3-77.

Now, therefore, under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of user in Land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

Termination of operation of pipeline from D.S. KHZ (K-187) to GGS-5

Name of Ministry	Villages	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Petroleum, Chemicals & Fertilizer	Ola, Island	434	18-2-78	24-3-77

[No. 12016/3/78-Prod-III]

का०आ० 1426.—भारत सरकार के अधिसूचना के द्वारा जैसाकि यहां संलग्न अनुसूची में प्रदर्शित किया गया है और पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (प्रयोक्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) अधिनियम, 1962 के खंड 6 के उपखंड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य के कलोल तेल क्षेत्र मे उक्त परिशिष्ट भूमि में वेधान स्थल स० के०डी०ई-3 (के-172) से जी०जी०एस०-5 तक पैट्रोलियम के लिए भूमि उपयोग के अधिकार प्राप्त किए गए है ।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपर्युक्त नियम के खंड 7 के उप-खंड (1) की धारा (1) में निर्दिष्ट कार्य दिनाक 5-7-1974 से समाप्त कर दिया गया है ।

अतः, अब पैट्रोलियम पाइप लाइन के नियम (प्रयोक्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) नियम, 1963 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी एतद्-द्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्ति की तिथि अधिसूचित करते है ।

अनुसूची

के०डी०ई०-3(के०-172) से जी०जी०एस०-5 तक पाइप लाइन कार्य की समाप्ति

मंत्रालय का नाम	गांव	का०आ० स०	भारत के राजपत्र मे प्रकाशन की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक	ईसन्ड	613	4-3-78	5-7-1974

[सं० 12016/3/78-प्रो० IV]

S.O. 1426. Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub-section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from d.s. KDE-3 (K-172) to G.G.S.-5 in Kalol oil field in Gujarat State.

And whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub section (1) of section 7 of the said Act on 5-7-1974.

Now, therefore, under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

Termination of operation of pipeline from D.S. KDE-3 (K-172) to G.G.S-5.

Name of Ministry	Villages	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Petroleum, Chemicals & Fertilizer	Island	613	4-3-78	5-7-1974

[No. 12016/3/78-Prod-IV]

का०आ० 1427.—भारत सरकार के अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में प्रदर्शित किया गया है और पैट्रोलियम और खनीज पाइप लाइन (प्रयोक्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) अधिनियम, 1962 के खंड 6 के उप-खंड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य के कलोल तेल क्षेत्र में उक्त परिशिष्ट भूमि में वेधन स्थल सं० सानन्द 1 और 33 से जी०जी०एस०एस०आई०पी० तक पैट्रोलियम के लिए भूमि उपयोग के अधिकार प्राप्त किए गए है ।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपर्युक्त नियम के खंड 7 के उपखंड (1) की धारा (1) में निर्दिष्ट कार्य दिनांक 23-12-74 से समाप्त कर दिया गया है ।

अतः, अब, पैट्रालियम पाइप लाइन के नियम (प्रयोक्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) नियम, 1963 के अन्तर्गत सक्षम प्रधिकारी एतद्-द्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्ति की तिथि अधिसूचित करते है ।

अनुसूची

सानन्द 1 और 33 से जी०जी०एस०एस०आई०पी० तक पाइप लाइन कार्य की समाप्ति

मंत्रालय का नाम	गांव	का०आ० सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक	जेटलज	436	18-2-78	23-12-74

[सं० 12016/3/78-प्रो०-V]

S.O.1427.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub-section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from d.s. Sanand 1 & 33 to GGS SIP in Kalol oil field in Gujarat State.

And whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub-section (1) of section 7 of the said Act on 23-12-74.

Now, therefore, under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of right of User in Land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

Termination of operation of pipeline from D.S. Sanand 1 & 33 to GGS SIP

Name of Ministry	Villages	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Petroleum, Chemicals & Fertilizer	Jethalaj	436	18-2-78	23-12-74

[No. 12016/3/78-Prod-V

का०आ० 1428.—भारत सरकार के अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में प्रदर्शित किया गया है और पैट्रोलियम और खनिज पाईप लाइन (प्रयोक्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) अधिनियम, 1962 के खंड 6 के उपखंड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य के कड़ी तेल क्षेत्र में उक्त परिशिष्ट भूमि में वेधान स्थल सं० एस० के०-2 से सी० टी० एफ० कड़ी तक पैट्रोलियम के लिए भूमि उपयोग के अधिकार प्राप्त किए गए है।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपयुक्त नियम के खण्ड 7 के उप-खंड (1) की धारा (1) में निर्दिष्ट कार्य दिनांक 21-2-77 से समाप्त कर दिया गया है।

अतः, अब, पैट्रोलियम पाइप लाइन के नियम (प्रयोक्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) नियम, 1963 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्ति की तिथि अधिसूचित करते है।

अनुसूची

एस० के०-2 से सी० टी० एफ० कड़ी तक पाइप लाइन कार्य की समाप्ति

मंत्रालय का नाम	गांव	का० आ० सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक	कड़ी	185	21-1-78	21-2-77

[सं० 12016(3)78-प्रो०-VI]

S.O.1428—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub-section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisiti on of Right of User in Land) Act, 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from d.s. SK-2 to C.T.F. Kadi in Kadi oil field in Gujarat State.

And whereas the Oil & Natural Gas Commissio n has terminated the operations referred to in clause (i) of sub-section (1) of section 7 of the said Act on 21-2-1977.

Now, therefore, under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of right of user in land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

Termination of operation of Pipeline from D.S. SK-2 to C.T.F. Kadi.

Name of Ministry	Villages	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Petroleum, Chemicals & Fertilizer	Kadi	185	21-1-1978	21-2-1977

[No. 12016/3/78-Prod. VI]

का०आ० 1429.—भारत सरकार के अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न, अनुसूची में प्रदर्शित किया गया है और पैट्रोलियम और खनीज पाइप लाइन (प्रयोक्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उप-खण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य के मेहसाना तेल क्षेत्र में उक्त परिशिष्ट भूमि में वेधान स्थल सं० एन० के० बी० क्यू० से डब्ल्यू० एच० आई-कड़ी-25 तक पैट्रोलियम के लिए भूमि उपयोग के अधिकार प्राप्त किए गए हैं।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपर्युक्त नियम के खण्ड 7 के उप-खण्ड (1) की धारा (1) में निर्दिष्ट कार्य दिनांक 29-3-77 से समाप्त कर दिया गया है।

अतः, अब, पैट्रोलियम पाइप लाइन के नियम (प्रयोक्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) नियम, 1963 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्ति की तिथि अधिसूचित करते हैं।

अनुसूची

एन० के० बी० क्यू० से डब्ल्यू० एच० आई० कड़ी-25 तक पाइप लाइन कार्य की समाप्ति

मंत्रालय का नाम	गांव	का० आ० सं०	भारत के राजपत्र में में प्रकाशन की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक	तेलावी	182	21-1-78	29-3-77

[सं० 12013/3/78-प्रो०-VII]

S.O. 1429—Whereas by the notification ofGcvern ment of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from d.s. MKBQ to WHI-kadi-25 in Mehsana oil field in Gujarat State.

And whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub section (1) of section 7 of the said Act on 29-3-77.

Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

Termination of operation of Pipeline from D.S. NKBQ to WHI-kadi-25

Name of Ministry	Villages	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Petroleum, Chemicals & Fertilizer	Telavi	182	21-1-78	29-3-77

[No. 12016/3/78-Prod. VII

का०आ० 1430.—भारत सरकार के अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में प्रदर्शित किया गया है और पैट्रोलियम और खनीज पाइप लाइन (प्रयोकिता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है गुजरात राज्य के मेहसाना तेल क्षेत्र में उक्त परिशिष्ट भूमि में वेधान स्थल सं० ऐस० सी० ऐ०, ऐस० डी० ऐम० से ऐस० बी०ऐच० तक पैट्रोलियम के लिए भूमि उपयोग के अधिकार प्राप्त किए गए हैं।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपर्युक्त नियम के खण्ड 7 के उप-खण्ड (1) की धारा (1) में निर्दिष्ट कार्य दिनांक 28-5-76 से समाप्त कर दिया गया है।

अतः अब पैट्रोलियम पाइप लाइन के नियम (प्रयोकिता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) नियम, 1963 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्ति तिथि अधिसूचित करते हैं।

अनुसूची

ऐस० सी० ऐ०, ऐस० डी० ऐम से ऐस० बी० ऐच तक पाइप लाइन कार्य की समाप्ति

मंत्रालय का नाम	गांव	का०आ०सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक	मेहसाणा नागलपुर कुकस	3542	19-11-77	28-5-76

[सं० 12016/3/78-प्रो०-VIII]

S. O. 1430.—Wherers by the notification of Government of India as shown in schedule appended hereto and issued under sub-section (1) of section 6 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from d s. SCA, SDM to SBH in Mehsana oil field in Gujarat State.

And whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub-section (1) of section 7 of the said Act on 28-5-76.

Now th refore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

Termination of Operation of Pipeline from D.S., SCA, SDM to SBH

Name of Ministry	Villages	S.O.No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Petroleum, Chemicals & Fertilizer	Mehsana Nagalpur Kukas	3542	19-11-77	28-5-76

[No. 12016/3/78-Prod.-VIII]

का०आ० 1431.—भारत सरकार के अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में प्रदर्शित किया गया है और पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (प्रयोकिता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) अधिनियम, 1962 के खंड 6 के उपखंड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है गुजरात राज्य के मेहसाणा तेल क्षेत्र में उक्त परिशिष्ट भूमि में वेधान स्थल सं० ऐस पी एल से एम के-64 तक पैट्रोलियम के लिए भूमि उपयोग के अधिकार प्राप्त किए गए हैं।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपर्युक्त नियम के खंड 7 के उपखंड (1) की धारा (1) में निर्दिष्ट कार्य दिनांक 3-6-76 से समाप्त कर दिया गया है।

अतः अब पैट्रोलियम पाइप लाइन के नियम (प्रयोकिता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) नियम, 1963 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्ति तिथि अधिसूचित करते हैं।

अनुसूची

एस० पी० एल० से एम के-64 तक पाइप लाइन कार्य की समाप्ति

मंत्रालय का नाम	गांव	का०आ० सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक	सूरज	180	21-1-78	3-6-76

[सं० 12016/3/78-प्रो०-IX]

S. O. 1421.—Whereas by the notification of Government of India as shown in schedule appended hereto and issued under sub-section (1) of section 6 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the

schedule appended thereto for the transport of petroleum from d s. SPL to MK-64 in Mehsana oils field in Gujarat State;

And whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub-section (1) of section 7 of the said Act on 3-6-76;

Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of right of user in land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

Termination of Operation of Pipeline from D.S. SPL to MK-64

Name of Ministry	Villages	S.O.No.	Date of publication in the Gazette of India.	Date of termination of operation
Petroleum, Chemicals & Fertilizer.	Suraj	180	21-1-78	3-6-76

[No. 12016/3/78-Prod. IX]

नई दिल्ली, 3 मई, 1978

का०आ० 1432.—यत. पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का०आ०सं० 842 तारीख 21-2-77 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था;

और यत: सक्षम प्रधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और आगे, यत केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमियो में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ;

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों मे उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है,

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार देती है कि उक्त भूमियो मे उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार मे विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग मे, सभी सपत्तियों से मुक्त रूप मे, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

कूप नं० के० डी० ई०-21 (के-184) से जी० जी० एस-5
राज्य—गुजरात . .जिला—हसाणा तालुका—मेकलोस

गांव	ब्लाक नं०	हेक्टर	एरीआई	सेन्टीआर
ईसड	680	0	21	45

[सं० 12016/9/76-एल और एल-I]

New Delhi, the 3rd May, 1978

S.O. 1432.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. No. 842 dated 21-2-77 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of right of user in land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under sub section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now therefore in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Acquisition of ROV from Well No KDR-21 (K-184) to GGS-V
State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol

Village	Block No.	Hect.	Are.	Centiare
Is and . .	682	0	21	45

[No. 12016/9/76-L & L-I]

का०आ० 1433.—यत. पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार अर्जन' अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का०आ०सं० 2344 तारीख 24-5-76 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था;

और यत: सक्षम प्रधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और आगे, यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है;

अब, अत. उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है,

और आगे उस धारा की अपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार मे विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी संपत्तों से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

पाइप लाइन डी०एस० 23 से जी०जी० एस तक

राज्य गुजरात	जिला: खेड़ा		तालुका: खम्भात क्षेत्रफल	
गांव	सर्वेक्षण नं०	हेक्-टेयर	एआर ई	सेंटी यर
जालापुर	कार्ट-ट्रैक	0	00	49
	181	0	07	84
	182	0	00	70
	179	0	07	84
	178	0	05	60
	180	0	00	84
	कार्ट-ट्रैक	0	00	49
नेजा	206	0	00	63
	205	0	08	40
	204	0	07	70
	200	0	11	90
	198	0	00	70
	कार्ट-ट्रैक	0	00	49
सोखदा	99	0	02	10
	114	0	01	40
	113	0	02	10
	112	0	02	80
	102	0	07	35
	103	0	07	70
	108/2	0	03	50
	108/1	0	04	20
	107	0	03	15
	कार्ट-ट्रैक	0	03	49
	24	0	05	95
	19/1	0	06	30
	11	0	25	20
	20/1	0	01	40
	कार्ट-ट्रैक	0	00	49
पाल्डी	36	0	09	10
	34	0	16	10

[सं० 12016/9/76-एल और एल-II]

S.O. 1433.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. No. 2344 dated 24-5-76 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of right of user in land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now therefore in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines ,

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from D.S. 23 to G.G.S.

State : Gujarat	District Kaira	Taluka : Cambay		
Village	Survey No.	Hect-are	Are	Centi-are
Zalapur . .	Cart-track	0	00	49
	181	0	07	84
	182	0	00	70
	179	0	07	84
	178	0	05	60
	180	0	00	84
	Cart-track	0	00	49
Neja . . .	206	0	00	63
	205	0	08	40
	204	0	07	70
	200	0	11	90
	198	0	00	70
	Cart-track	0	00	49
Sokhada .	99	0	02	10
	114	0	01	40
	113	0	02	10
	112	0	02	80
	102	0	07	35
	103	0	07	70
	108/2	0	03	50
	108/1	0	04	20
	107	0	03	15
	Cart-track	0	00	49
	24	0	05	95
	19/1	0	06	30
	11	0	25	20
	20/1	0	01	40
	Cart-track	0	00	49
Paldi . . .	36	0	09	10
	34	0	16	10

[No. 12016/9/76-L & L-II]

का० आ० 1434 —यत पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का०आ०सं० 843 तारीख 21-2-77 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार का पाइप लाइनों के बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, यत उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी संपत्तियों से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

कुआ नं० 150 को कुआ नं० के-34 से जोड़ने के लिए पाइपलाइन
राज्य-गुजरात ; जिला-मेहसाना ; तालुका-कैलोल

गांव	खंड	हैक्टेयर	आर्क	सेन्टायर
धमासाना	720	0	03	90

[सं० 12016/9/76-एल०एंड एल-3]

S.O. 1434.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. No. 841 dated 21-2-1977 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of right of user in land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government ,

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now therefore in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Well No. 150 to Line of Well No. K-34
State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kaoll

Village	Block No.	Hect-are	Are	Cen-tiare
Dhamasana	720	0	03	90

[No. 12016/9/76-L & L-III]

का० आ० 1435.—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पैट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 841 तारीख 21-2-77 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों के बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी संपत्तियों से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

डी० एस० के० डी० ई०-20 जी० जी० एस०-4 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कलोल

गांव	ब्लोक नं०	हेक्टेयर	एआरई	सेन्टीयर
धामासना	818	0	07	50
	826	0	09	21
	827	0	10	13
	828	0	01	00
	829	0	23	55
	830	0	01	65
	829	0	07	20
	834	0	10	05
	881	0	09	90

[सं० 12016/9/71 प्रोडक्शन-IV]

S.O. 1435.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. No. 841 dated 21-2-77 under sub-section(1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of right of user in land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline ;

And Whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now therefore in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines ;

And further in exercise of power confered by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commision free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from D.S. KDE—20 to GGS IV
State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol

Village	Block No.	Hect-are	Are	Cen-tiare
Dhamasana	818	0	07	50
	826	0	09	21
	827	0	10	13
	828	0	01	00
	829	0	23	55
	830	0	01	65
	829	0	07	20
	834	0	10	05
	881	0	09	90

[No. 12016/9/76—L & L-]VI

का० आ० 1436--यत. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में सलाया पोर्ट से उत्तर प्रदेश में मथुरा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाईप लाइन इण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यत. यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनो को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची मे वर्णित भूमि मे उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अत. अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमे उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि मे हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, सलाया-मथुरा पाईप लाइन प्रोजेक्ट, बी-18, शिवमार्ग, बनीपार्क, जयपुर-6 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनो के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

तहसील : बाली जिला : पाली राज्य : राजस्थान

ग्राम	खसरा नं०	क्षेत्रफल		
		हेक्टर	ऐयर	वर्गमीटर
कोट	216/1 मिन	0	00	81
	441	0	08	09

[सं० 12020/2/78-प्रोड० I]

S.O. 1436.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Salaya Port in Gujarat to Mathura in Uttar Pradesh Pipelines should be laid by the Indian Oil Corporation Limited.

And whereas it appears that for the Purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto :

Now,therefore, in exercise of the Powers conferred by Subsection (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declare its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Salaya-Koyali-Mathura Pipeline project, B-18, Shiv Marg, Bani Park, Jaipur-6.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Tehsil : Bali District : Pali State : Rajasthan

Village	Khasra No.	Area		
		H	A	Sq. M.
Kot	216/1 min	0	00	81
	441	0	08	09

[No. 12020/2/78—Prod.]

का०आ० 1437---यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में सलाया पोर्ट से उत्तर प्रदेश में मथुरा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाईप लाइन इण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यत. यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि मे उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन(भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमे उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद् द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि मे हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, सलाया-मथुरा पाईप लाइन प्रोजेक्ट, बी-18, शिवमार्ग, बनीपार्क, जयपुर-6 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट. यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

तहसील : ब्यावर जिला : अजमेर राज्य . राजस्थान

ग्राम	खसरा नं०		क्षेत्रफल		
	साबिक	हाल	हैक्टर	ऐयर	वर्गमीटर
केसरपुरा	240 241	316	0	08	90

[सं० 12020/2/78-प्रोड०II]

S.O. 1437.---Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Salaya Port in Gujarat to Mathura in Uttar Pradesh Pipelines should be laid by the Indian Oil Corporation Limited.

And whereas it appears that for the Purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Subsection (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declare its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Salaya-Koyali-Mathura Pipeline Project, B-18, Shiv Marg, Bani Park, Jaipur-6. And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Tehsil : Beawar District : Ajmer State : Rajasthan

Village	Khasra No		Area		
	Old	New	H.	A.	Sq M.
Kesarpura	240 241	316	0	08	90

[No. 12020/2/78--Prod. II]

का०आ० 1438—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में सलाया पोर्ट से उत्तर प्रदेश मे मथुरा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाईप लाइन इण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यत यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची मे वर्णित भूमि मे उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962(1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमे उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद् द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि मे हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, सलाया-मथुरा पाइप लाइन प्रोजेक्ट, बी-18, शिवमार्ग, बनीपार्क, जयपुर-6 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिश हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

तहसील : देसूरी जिला : पाली राज्य : राजस्थान

ग्राम	खसरा नं०	क्षेत्रफल		
		हेक्टर	ऐयर	वर्ग मीटर
सिवास	129	0	06	35
	16	0	01	61

[सं० 12020/2/78-प्रोड० III]

S.O. 1438.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Salaya Port in Gujarat to Mathura in Uttar Pradesh Pipelines should be laid by the Indian Oil Corporation Limited.

And whereas it appears that for the Purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declare its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Salaya-Koyali-Mathura Pipeline Project, B-18, Shiv Marg, Bani Park, Jaipur-6.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Tehsil : Desuri District : Pali State : Rajasthan

Village	Khasra No.	Area		
		H.	A.	Sq. M.
Siwas	129	0	06	35
	16	0	01	61

[No. 12020/2/78—Prod. III]

का०आ० 1439—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य मे सलाया पोर्ट से उत्तर प्रदेश मे मथुरा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाईप लाइन इण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यत यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची मे वर्णित भूमि मे उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमे उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि मे हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाइन बिछाने के लि आक्षेप सक्षम प्राधिकारी इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, सलाया-मथुरा पाईप लाइन प्रोजेक्ट, बी-18, शिवमार्ग बनीपार्क, जयपुर-6 का इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनो के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिश हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

तहसील : देसूरी जिला : पाली राज्य : राजस्थान

ग्राम	खसरा नं०	क्षेत्रफल		
		हेक्टर	ऐयर	वर्ग मीटर
कोटड़ी	36	0	03	01
	38	0	14	63

[सं० 12020/2/78-प्रोड० IV]

S.O. 1439.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Salaya Port in Gujarat to Mathura in Uttar Pradesh Pipelines should be laid by the Indian Oil Corporation Limited.

And whereas it appears that for the Purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declare its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Salaya-Koyali-Mathura Pipeline Project, B-18, Shiv Marg, Bani Park, Jaipur-6.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Tehsil : Desuri District : Pali State : Rajasthan

Village	Khasra No	Area		
		H.	A.	Sq M.
Kotari	36	0	03	01
	38	0	14	63

[No. 12020/2/78 Prod. IV]

का०आ० 1440.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में सलाया पोर्ट से उत्तर प्रदेश में मथुरा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाईप लाईन इण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, सलाया-मथुरा पाईप लाइन प्रोजेक्ट, बी-18, शिवमार्ग, बनीपार्क, जयपुर-6 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

तहसील : रायपुर	जिला : पाली		राज्य : राजस्थान	
ग्राम	खसरा नं०	क्षेत्रफल		
		हेक्टर	ऐयर	वर्ग मीटर
सैंदड़ा	128	0	15	81
	563	0	24	02
	513	0	11	33
	512	0	08	47
	510	0	03	79
	511	0	05	69
	528	0	03	79
	527	0	04	68
	405	0	00	38
	406	0	04	93
	407	0	02	02
	398	0	06	32

[सं० 12020/2/78-प्रोड०-V]

S.O. 1440.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Salaya Port in Gujarat to Mathura in Uttar Pradesh Pipelines should be laid by the Indian Oil Corporation Limited.

And whereas it appears that for the Purpose of laying such piplines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the Powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declare its intention to acquire the right of user therein ,

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Salaya-Koyali-Mathura Pipeline Project, B-18, Shiv Marg, Bani Park, Jaipur-6.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practioner.

SCHEDULE

Tehsil : Raipur	District : Pali	State : Rajasthan		
Village	Khasra No.	Area		
		H.	A.	Sq. M.
Sendra	128	0	15	81
	563	0	24	02
	513	0	11	33
	512	0	08	47
	510	0	03	79
	511	0	05	69
	528	0	03	79
	527	0	04	68
	405	0	00	38
	406	0	04	93
	407	0	02	02
	398	0	06	32

[No 12020/2/78-Prod-V]

का० आ० 1441.—यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित मे यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य मे सलाया पोर्ट से उत्तर प्रदेश मे मथुरा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाईप लाईन इण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यत. यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनो को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमे उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि मे हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, सलाया-मथुरा पाईप लाईन प्रोजेक्ट, बी-18, शिव मार्ग, बनी पार्क, जयपुर-6 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनो के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिश हो या किसी विधि व्यवधायी की मार्फत ।

अनुसूची

तहसील : रायपुर	जिला : पाली		राज्य : राजस्थान	
ग्राम	खसरा नं०	क्षेत्रफल		
		हेक्टर	ऐयर	वर्ग मीटर
सबलपुरा प्रथम	306	0	01	03
	305	0	00	53
	298	0	01	46
	296	0	02	92
	276	0	00	34
	254	0	01	46

[सं० 12020/2/78-प्रोड०-VI]

S.O. 1441.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Salaya Port in Gujarat to Mathura in Uttar Pradesh Pipelines should be laid by the Indian Oil Corporation Limited.

And whereas it appears that for the Purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declare its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Salaya-Koyali-Mathura Pipeline Project, B-18, Shiv Marg, Bani Park, Jaipur-6.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Tehsil : Raipur District : Pali, State : Rajasthan

Village	Khasra No.	Area H	A	Sq. M
Sabalpura(T)	306	0	01	03
	303	0	00	53
	298	0	01	46
	296	0	02	92
	276	0	00	34
	254	0	01	46

[No. 12020/2/78-Prod. VI]

का०आ० 1442.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में सलाया पोर्ट से उत्तर प्रदेश में मथुरा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाईप लाईन इण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, सलाया-मथुरा पाईप लाईन प्रोजेक्ट, बी-18, शिव मार्ग, बनी पार्क, जयपुर-6 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

तहसील : आबू रोड जिला : सिरोही राज्य : राजस्थान

ग्राम	खसरा नं०	क्षेत्रफल हेक्टर	ऐयर	वर्ग-मीटर
सांतपुर	617	0	02	53
	618	0	05	06
	637	0	02	53

[सं० 12020/2/78-प्रोड०-VII]

S.O. 1442.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Salaya Port in Gujarat to Mathura in Uttar Pradesh Pipelines should be laid by the Indian Oil Corporation Limited.

And whereas it appears that for the Purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the Powers conferred by Sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declare its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelnies under the land to the Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Salaya-Koyali-Mathura Pipeline Project, B-18, Shiv Marg, Bani Park, Jaipur-6.

And every person making such an objection shall also state specifically whether the wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Tehsil : Abu Road District : Sirohi State : Rajasthan

Village	Khasra No.	Area H	A	Sq. M
Santpur	617	0	02	53
	618	0	05	06
	637	0	02	53

[No. 12020/2/78-Prod. VII]

का० आ० 1443.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में सलाया पोर्ट से उत्तर प्रदेश में मथुरा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाईप लाईन इण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962(1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, सलाया-मथुरा पाईप लाइन प्रोजेक्ट, बी-18, शिव मार्ग, बनी पार्क, जयपुर-6 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट, यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

तहसील : सिकराय जिला : जयपुर राज्य : राजस्थान

ग्राम	खसरा नं०	क्षेत्रफल		
		हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
सिकराय	1536	0	05	06

[सं० 12020/2/78-प्रोड०-VIII]

S.O. 1443.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Salaya Port in Gujarat to Mathura in Uttar Pradesh Pipelines should be laid by the Indian Oil Corporation Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central, Government hereby declare its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Salaya-Koyali-Mathura Pipeline Project, B-18, Shiv Marg, Bani Park, Jaipur-6.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Tehsil : Sikrai District : Jaipur State : Rajasthan

Village	Khasra No.	Area		
		H	A	Sq. M
Sikrai	1536	0	05	06

[No. 12020/2/78-Prod. VIII]

का० आ० 1444—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में सलाया पोर्ट से उत्तर प्रदेश में मथुरा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाईप लाईन इण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, सलाया-मथुरा पाईप लाइन प्रोजेक्ट, बी-18, शिव मार्ग, बनी पार्क, जयपुर-6 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

तहसील रायपुर जिला पाली राज्य : राजस्थान

ग्राम	खसरा नं०	क्षेत्रफल		
		हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
सराधना	454	0	00	38
	455	0	01	20
	456	0	02	40
	457	0	04	10
	467	0	07	39
	470	0	00	64
	474	0	05	77

[सं० 12020/2/78-प्रोड० IX]

S.O. 1444.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Salaya Port in Gujarat to Mathura in Uttar Pradesh Pipelines should be laid by the Indian Oil Corporation Limited.

And whereas it appears that for the Purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the Powers conferred by Sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declare its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said Land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Salaya-Koyali-Mathura Pipeline Project, B-18, Shiv Marg, Bani Park, Jaipur-6.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Tehsil : Raipur	District : Pali	State : Rajasthan		
		Area		
Village	Khasra No.	H	A	Sq. M
Saradhana	454	0	00	38
	455	0	01	20
	456	0	02	40
	457	0	04	10
	467	0	07	39
	470	0	00	64
	474	0	05	77

[No. 12020/2/78-Prod. IX]

नई दिल्ली, 4 मई, 1978

का०आ० 1445.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 175 तारीख 30-12-77 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी संबंधों से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

कूप नं० एस० के०-1 (कड़ी-45) से सी०टी० एफ० कलोल तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात	जिला: मेहसाना	तालुका : कड़ी		
गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	एआरई	सेण्टीयर
कड़ी	1831/2	0	06	00
	1833	0	03	90
	कार्ट ट्रैक	0	00	90
	1836	0	13	55
	1838	0	11	40
	1852	0	12	75
	1851	0	06	75
	1853	0	05	40

[सं० 12016/2/77-प्रो० अनुभाग I]

New Delhi, the 4th May, 1978

S.O. 1445.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, Chemicals & Fertilizer, S O. No. 175 dated 30-12-77 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of right of user in land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now therefore in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquire for laying the pipelines ;

And further in exercise of powers conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Laying Pipeline from Well No. SK-1 (Kadi-45) to CTF Kadi

State : Gujarat	District Mehsana	Taluka : Kadi		
Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
1	2	3	4	5
Kadi	1831/2	0	06	00
	1833	0	03	90

1	2	3	4	5
KDAI—Contd.	Cart track	0	00	90
	1836	0	13	55
	1838	0	11	40
	1852	0	12	75
	1851	0	06	75
	1853	0	05	40

[No. 12016/2/77-Prod. I]

का०आ० 1446.—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का०आ० सं० 176 तारीख 30-12-77 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना के संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों मे उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियो मे उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बंधकों से मुक्त रूप मे, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

कूप नं० के० ई० एक्स० 11 से कूप नं० के० ई० एक्स-5 की लाइन तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज : गुजरात जिला व तालुका : गांधी नगर

गांव	ब्लाक नं०	हैक्टेयर	एआरई	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
जमीयतपुरा	53	0	04	35
	52	0	07	95
	59	0	09	00
	58	0	06	90
	66	0	03	69

1	2	3	4	5
जमीयतपुरा—जारी	65	0	14	72
	69	0	09	00
	70	0	02	25
	197	0	12	00

[सं० 12016/2/77-प्रोड०-II]
के० पी० जेठानी, अवर सचिव

S.O. 1446.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, Chemicals & Fertilizer, S.O. No. 176 dated 30-12-77 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of right of user in land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government ,

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now therefore in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquire for laying the pipelines ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government driects that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from well No. KEX. 11 to Line of well No. KEX.5

State : Gujarat Dist & Taluka : Gandhinagar

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Jamiyatpura	53	0	04	35
	52	0	07	95
	59	0	09	00
	58	0	06	90
	66	0	03	69
	65	0	14	72
	69	0	09	00
	70	0	02	25
	197	0	12	00

[No. 12016/2/77-Prod. II]
K.P. JETHANI, Under Secy.

विदेश मंत्रालय

(कौंसली अनुभाग)

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 1978

का०आ० 1447—राजनयिक एवं कोंसली अधिकारी (शपथ एवं शुल्क) अधिनियम 1948 (1948 का 41) की धारा 2 के खंड (क) के अनुपालन में केन्द्रीय सरकार, इसके द्वारा भारत के राजदूतावास टोकियो (जापान) में सहायक, श्री एम० पी० वर्मा को तत्काल से कोंसली एजेंट के रूप में कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

[सं० टी 4330/1/77]
जी० एफ० नाइगामवाला, अवर सचिव

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(Consular Section)

New Delhi, the 26th April, 1978

S.O. 1447.—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oath & Fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby authorises Shri S. P. Verma, Assistant in the Embassy of India, Tokyo, Japan, to perform the duties of a Consular Agent, with immediate effect.

[No. T. 4330/1/77]
J. F. NAEGAMVALA, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 3 मई, 1978

का०आ० 1448.—यत भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की 22 दिसम्बर, 1966 की अधिसूचना संख्या 19-18/66, एम पी टी द्वारा केन्द्रीय सरकार ने निदेश दिया है कि भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) के प्रयोजनों के लिए "सेंट लूइस यूनिवर्सिटी, स्कूल आफ मैडिसिन, यू एस ए द्वारा प्रदत्त एम० डी० चिकित्सा अर्हता" मान्य चिकित्सा अर्हता होगी,

और यत डा० सिस्टर मेरी फिलीपीन बेलेगर जिनके पास उक्त अर्हता है, धर्मार्थ कार्य के प्रयोजनों के लिए फिलहाल सेंट जोसफ अस्पताल बारामूला, कश्मीर के साथ सम्बद्ध है,

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (1) के परन्तुक के भाग (ग) का पालन करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा,—

(1) सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि अथवा

(2) उस अवधि को जब तक डा० सिस्टर मेरी फिलीपीन बेलेगर उक्त सेंट जोसफ अस्पताल, बारामूला, कश्मीर के साथ सम्बद्ध रहती है जो भी कम हो वह अवधि विनिर्दिष्ट करती है जिसमें पूर्वोक्त डा० मेडिकल प्रेक्टिस कर सकेंगी।

[सं० वी 11016/1/78-एम ई (पी)]
आर० वी० श्रीनिवासन, उप सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

ORDER

New Delhi, the 3rd May, 1978

S.O. 1448.—Whereas by the notification of the Government of India in the late Ministry of Health No. 19-18/66-MPT, dated the 22nd December, 1966, the Central Government has directed that the medical qualification, "M.D., granted by the St. Louis University, School of Medicine, U.S.A.", shall be recognised medical qualification for the purposes of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956);

And whereas Dr. Sr. Mary Phillippine Balagour who possesses the said qualifications is for the time-being attached to the St. Joseph's Hospital, Baramulla, Kashmir, for the purposes of charitable work;

Now, therefore, in pursuance of clause (c) of the proviso to sub-section (1) of section 14 of the said Act, the Central Government hereby specifies—

(i) a further period of two years from the date of publication of this order in the Official Gazette, or

(ii) the period during which Dr. Sr. Mary Phillippine is attached to the said St. Joseph's Hospital, Baramulla, Kashmir, whichever is shorter, as the period to which the medical practice by the aforesaid doctor shall be limited.

[No. V. 11016/1/78-M E.(P)]
R. V. SRINIVASAN, Dy. Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 3 मई, 1978

का० आ० 1449.—नाविक भविष्य निधि योजना, 1966 के पैरा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं० का०आ० 320, दिनांक 9-5-1977 को अधिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सरकार नाविक भविष्य निधि के न्यासी मण्डल के परामर्श से प्रशासनिक प्रभार लेखा में अधिशेष पर विचार करते हुए 1-4-1978 से उक्त योजना के पैरा 35 के अधीन देय प्रशासनिक प्रभार की दर भविष्य निधि अंशदान का 1.5 प्रतिशत नियत करती है।

[सं० एम० डब्ल्यू० एस० (45)/78-एमटी]
श्रीमती बी० निर्मल, अवर सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 3rd May, 1978

S.O. 1449.—In exercise of the powers conferred by paragraph 37 of the Seamen's Provident Fund Scheme, 1966 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping & Transport (Transport Wing) No. S.O. 320, dated 9th May, 1977 the Central Government in consultation with the Board of Trustees of the Seamen's Provident Fund and considering the surplus in the Administrative Charge Account, hereby fixes, with effect from the 1st April, 1978 the Administrative Charge payable under paragraph 35 of the said Scheme at 1.5 per cent of the Provident Fund contributions.

[No. MWS(45)/78-MT]
SMT. B. NIRMAL, Under Secy.

का० आ० 1450.—मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 128 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 3796, दिनांक 23 नवम्बर, 1977 का अधिक्रमण करते हुए, केन्द्रीय सरकार किसी व्यक्ति द्वारा लिए गए श्वास के एक या इससे अधिक नमूनों पर परीक्षण करके उसके रक्त में अल्कोहल की विद्यमानता का पता लगाने के लिए निम्नलिखित प्रकार के यंत्रों को

(जिन्हें इसके बाद श्वास विश्लेषण कहा गया है) श्वास परीक्षण के लिए अनुमोदित करती है, अर्थात् :—

(1) यंत्र I :—श्वास विश्लेषक में निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :—

(क) द्रव्य से भरी एक सूचक नली जिसका रंग नली में किसी अल्कोहलमय पदार्थ के श्वसन के कारण अल्कोहल वाष्पों के साथ संपर्क में आने से बदल जाएगा :

परन्तु सूचक नली की शैल्फ-अवधि एक वर्ष कम नहीं होगी ताकि इस अवधि के लिए एकत्र किए गए श्वास विश्लेषक का कार्य निष्पादन किसी भी प्रकार नवनिर्मित सूचक नली के कार्य से भिन्न न हो,

(ख) विषहीन प्लास्टिक द्रव्य से बनी एक मुखिका (माउथ-पीस),

(ग) पोलीथीन का बना हुआ एक लिटर आयतन का एक स्फीतपूर्ण थैला (पूरी तरह से फुलाए जाने पर) जिसके मुख पर एक मुखिका हो।

(2) यंत्र II—श्वास विश्लेषक में निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :—

(क) द्रव्य से भरी एक सूचक परीक्षण नली जिसका रंग नली में किसी पदार्थ के अल्कोहल वाष्पो के साथ संपर्क में आने के कारण बदल जाएगा,

(ख) एक मुखिका,

(ग) वर्ण ग्रीवा सहित और निर्धारित क्षमता से युक्त श्वसन पीठ (ब्रैथ बैक)।

(3) यंत्र III—श्वास विश्लेषक में निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :—

(क) पीले अभिकर्मक (री-अजैंट) से भरे एक सूचक नली जिसके दोनों सिरे फ्यूज किए हुए हों, जिसका रंग नली में किसी अल्कोहलमय पदार्थ के श्वसन के कारण अल्कोहल वाष्पों के साथ संपर्क में आने से बदल जाएगा :

परन्तु सूचक नली की शैल्फ अवधि तीन वर्षों से कम नही होगी ताकि इस अवधि के लिए एकत्र किए गए श्वास विश्लेषक का कार्य निष्पादन किसी भी प्रकार नवनिर्मित सूचक नली के कार्य से भिन्न न हो,

(ख) एक मुखिका,

(ग) स्फीतपूर्ण थैला जिसके मुख पर एक मुखिका हो और जिसे भारी स्वराघात से अभिनिर्धारित किया गया हो।

[एफ० सं० टी जी एम (20)/77]

S.O. 1450.—In exercise of the powers conferred by the Explanation to section 128A of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport No. S.O. 3796, dated the 23rd November, 1977, the Central Government hereby approves the following types of devices (hereinafter referred to as the breath analyser), for the purpose of obtaining an indication of the presence of alcohol in a person's blood by means of a test carried out, on one or more specimens of breath provided by that person, for the purpose of breath tests, namely :—

(1) Device I.—The breath analyser shall comprise the following, namely :—

(a) An indicator tube containing material which would undergo change of colour when in contact with alcohol vapours on breathing of an alcoholic subject into the tube :

Provided that the shelf-life of the indicator tube shall not be less than one year, so that the performance of the breath analyser stored for this period shall in no way be different from that of a freshly made indicator tube ;

(b) a mouth-piece made of non-toxic plastic material;

(c) an inflatable bag of volume of 1 litre, when fully inflated, made of polythene and attached with the mouth-piece at the opening.

(2) Device II.—The breath analyser shall comprise the following, namely :—

(a) An indicator test tube containing material which would undergo change of colour when in contact with alcohol vapours on dealing with an alcoholic subject into the tube ;

(b) a mouth-piece;

(c) a breath back with a colour neck and having a fixed capacity.

(3) Device III.—The breath analyser shall comprise the following, namely :—

(a) An indicator tube fused at both ends and containing a yellow reagent which would undergo change of colour when in contact with alcohol vapours on breathing of an alcoholic subject into the tube :

Provided that the shelf-life of the indicator tube shall not be less than three years, so that the performance of the breath analysis stored for this period shall in no way be different from that of a freshly made indicator tube ;

(b) a mouth-piece ;

(c) an inflatable bag of and attached with a mouth-piece at the opening and further identified by a broad weight bang.

[F. No. TGM(20/77]

नई दिल्ली, 4 मई, 1978

का०आ० 1451सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (1950 का 64) की धारा 44 की उपधारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा दिल्ली परिवहन निगम (सदस्य) नियम, 1973 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमो का नाम दिल्ली परिवहन निगम (सदस्य) संशोधन नियम, 1978 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 दिल्ली परिवहन निगम (सदस्य) नियम, 1973 में, नियम 7 के उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए, अर्थात् :—

"(2) गैर-सरकारी सदस्य निगम की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए पचास रुपये और अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत नियुक्त निगम की किसी समिति की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए चालीस रुपये का पारिश्रमिक पाने का अधिकारी होगा :

परन्तु यदि कोई ऐसा सदस्य एक ही दिन में निगम की बैठक तथा निगम की किसी समिति की बैठक में उपस्थित होता है तो वह इन बैठकों में उपस्थित होने के लिए केवल पचास रुपये का पारिश्रमिक पाने का अधिकारी होगा।

परन्तु यह भी कि गैर-सरकारी सदस्य को किसी भी महीने के दौरान देय कुल पारिश्रमिक तीन सौ रुपये से अधिक नहीं होगा।"

[फा० सं० टी जी डी (32)/77]

एन० ए० ए० नारायणन, उप सचिव

New Delhi, the 4th May, 1978

S.O. 1451.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of sub-section (2), of section 44 of the Road Transport Corporations Act, 1950 (64 of 1950), the Central, Government hereby makes the following rules further to amend the Delhi Transport Corporation (Members) Rules, 1973, namely :—

1. (1) These Rules may be called the Delhi Transport Corporation (Members) Amendment Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Delhi Transport Corporation (Members) Rules, 1973, for sub-rule (2) of rule 7 the following shall be substituted, namely :—

"(2) A non-official member shall be entitled to a fee of fifty rupees for attending each meeting of the Corporation and to a fee of forty rupees for attending each meeting of a Committee of the Corporation appointed under section 12 of the Act :

Provided that where any such member attends on the same day a meeting of the Corporation and a meeting of the Committee of the Corporation, he shall be entitled only to a fee of fifty rupees for attending such meetings :

Provided further that the aggregate amount of the fee payable to a non-official member during any month shall not exceed three hundred rupees."

[File No. TGD(32)/77]
N. A. A. NARAYANAN, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 5 मई, 1978

का०आ० 1452.—राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड नियम, 1960 के नियम 3 के साथ पठित व्यापार पोत अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित सदस्यों के राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड की स्थापना करती है और श्री विनोद भाई बी० सेठ, संसद सदस्य को उक्त बोर्ड का अध्यक्ष नामित करती है, अर्थात् :—

1. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया 2. श्री मनोरंजन भक्त 3. श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर 4. श्री विनोदभाई बी० सेठ	लोक सभा द्वारा निर्वाचित
5. श्री माधवराव ए० वाघ 6. श्री रमेश कुमार जैडका 7. सचिव, नौवहन और परिवहन मंत्रालय या उसके द्वारा नामित जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे न हो। 8. सचिव, वाणिज्य मंत्रालय या उसके द्वारा नामित जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे का न हो। 9. जल सेना का उपाध्यक्ष, जल सेना मुख्यालय रक्षा मंत्रालय। 10. वित्त सलाहकार, नौवहन और परिवहन मंत्रालय	केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि
11. नौवहन महानिदेशक, बम्बई	
12. अध्यक्ष, भारतीय नौवहन निगम लि०, बम्बई	
13. श्री एन० एच० धुंजीभाई 14. कैप्टेन जे० सी० आनन्द	पोत-स्वामियों के प्रतिनिधि
15. श्री के० पी० कोल्हा	भारतीय समुद्री संघ
16. श्री लीयो बर्नेस 17. श्री असीत मित्रा	नाविकों के प्रतिनिधि
18. श्री बी० डी० चौगले	अखिल भारतीय वणिक परिय
19. श्री के० के० बिरला	फैडरेशन आफ इंडियन चैम्बरज आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री
20. श्री डी० एम० पारिख	पाल पोत उद्योग

2 केन्द्रीय सरकार श्री एम० वाला, उप महानिदेशक, नौवहन को उक्त बोर्ड का सचिव नियुक्त करती है।

[सं० एम० एस० बी०-10/77-एमडी]
एस० रामचन्द्र राव, अवर सचिव

New Delhi, the 5th May, 1978

S.O. 1452.—In exercise of powers conferred by section 4 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), read with rule 3 of the National Shipping Board Rules, 1960, the Central Government hereby establishes a National Shipping Board Consisting of the following members and nominates Shri Vinodbhai B. Sheth, M.P. to be the Chairman of the said Board, namely :—

1. Shri Arjun Singh Bhadoria 2. Shri Manoranjan Bhakta 3. Shrimati Ahilya P. Rangnekar 4. Shri Vinodbhai B. Sheth	Elected by the Lok Sabha.
5. Shri Madhavrao A. Wagh 6. Shri Romesh Kumar Jaidka 7. Secretary, Ministry of Shipping & Transport or his nominee not below the level of Joint Secretary 8. Secretary, Ministry of Commerce or his nominee not below the level of Joint Secretary. 9. Deputy Chief of Naval Staff, Naval Headquarters, Ministry of Defence. 10. Financial Adviser, Ministry of Shipping and Transport. 11. Director General of Shipping Bombay.	Central Government resprcsentatives.
12. The Chairman, Shipping Corporation of India Ltd., Bombay.	
13. Shri N.H. Dhunjibhoy 14. Capt. J.C. Anand	Representatives of Shipowners.
15. Shri K.P. Kolah	Maritime Union of India.
16. Shri Leo Barnes 17. Shri Asit Mitra	Representatives of Seamen.
18. Shri V.D. Chowgule	All India Shippers Council.
19. Shri K.K. Birla	Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry..
20. Shri D.M. Parekh	Sailing Vessels Industry.

2. The Central Government appoints Shri M. Wala, Deputy Director-General of Shipping to be the Secretary of the said Board.

[No. MSB-10/77(MD)]
S. RAMACHANDRA RAO, Under Secy.

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1978

का० आ० 1453.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति जी एतद्द्वारा रेल कर्मचारी (अनु-

अनुशासन और अपील) नियम 1968 में और आगे संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

1 (1) ये नियम रेल कर्मचारी (अनुशासन और अपील) संशोधन नियम, 1978 कहे जायेंगे।

(2) ये राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2 रेल कर्मचारी (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 के नियम 9 मे।

(1) वर्तमान उप-नियम (9) के स्थान पर 9(क) लिखा जायेगा।

(2) 9(क) के पश्चात् निम्नलिखित वाक्यांश अन्तर्विष्ट करे —

"(ख) रेल कर्मचारी अपने अभ्यावेदन के मामलों मे किसी सेवा निवृत्त रेल कर्मचारी की सहायता ले सकते है बशर्ते कि यह इस मामले में राष्ट्रपति जी द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य या विशेष आदेशों मे दी गयी शर्तों के अधीन हो"।

[म० ई (डी एण्ड ए) 77 आर जी 6-30]
पी० एन० मोहिले, सचिव

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 7th April, 1978

S.O. 1453.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968, namely,

1. (1) These rules may be called the Railway Servants (Discipline and Appeal) Amendment Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 9 of the Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968 ;

(1) the existing sub-rule (9) shall be lettered as 9(a).

(2) The following clause shall be inserted after 9(a)—

"(b) The Railway servant may also present his case with the assistance of a retired railway servant, subject to such conditions as may be specified by the President from time to time by general or special order in this behalf."

[No. E(D&A)77RG6-30]
P. N. MOHILE, Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 मई, 1978

का० आ० 1454 केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० 4531, तारीख 15 नवम्बर, 1976 के अनुक्रम मे कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श करने के पश्चात्, कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग) के अधीन, एकीकृत मात्स्यकी परियोजना, एनकुलम के बर्फ एवं हिमीकरण संयंत्र, कर्मशालाएं और शिपयेज, इलैक्ट्रानिकी अनुभाग, प्रसंस्करण अनुभाग और गियर अनुभाग के नियमित कर्मचारियों को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से, 5 सितम्बर, 1977 से 30 जून, 1978 तक, जिसमे यह दिन भी सम्मिलित है, छूट देती है ।

2. पूर्वोक्त छूट की शर्तें निम्नलिखित है, अर्थात् —

(1) पूर्वोक्त कारखाना, जिसमे कर्मचारी नियोजित है, एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम और पदाभिधान दिखाए जाएंगे;

(2) इस छूट के होते हुए भी, कर्मचारी उक्त अधिनियम के अधीन ऐसी सुविधाएं प्राप्त करते रहेंगे, जिनको पाने के लिए वे इस अधिसूचना द्वारा दी गई छूट के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व संदत्त अभिदायों के आधार पर हकदार हो जाते;

(3) छूट प्राप्त अवधि के लिए यदि कोई अभिदाय पहले ही किए जा चुके हो तो वे वापिस नही किए जाएंगे;

(4) उक्त कारखाने का नियोजक, उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अवधि' कहा गया है), ऐसी विवरणियां, ऐसे प्ररूप मे और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी,

(5) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या निगम का इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी —

(i) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ; या

(ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950, द्वारा यथाअपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नही, या

(iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दिए गए उन फायदों को, जिसके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद मे और वस्तु रूप मे पाने का हकदार बना हुआ है या नही; या

(iv) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान जब उक्त कारखाने, के संबंध में अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्ही उपबंधों में से किसी का अनुपालन किया गया था या नही;

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा —

(क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी आवश्यक समझता है, या

(ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी से अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसी लेखा बहियां और अन्य दस्तावेज, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करे और उनकी परीक्षा करने दे, या उन्हे ऐसी जानकारी दे जिसे वे आवश्यक समझते है; या

(ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक की, उसके अभिकर्ता या सेवक की, या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना; या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उससे उद्धरण लेना ।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस मामले में पूर्वपक्षी प्रभाव से छूट देनी आवश्यक हो गई है, क्योंकि छूट के लिये आवेदन पत्र कार्रवाई करने मे समय लगा । तथापि

यह प्रमाणित किया जाता है कि इन कारखानों के कर्मचारी छूट के पात्र हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट देने से किसी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[सं० एस० 38014/36/76-एच०आई०]

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 4th May, 1978

S.O. 1454.—In exercise of the powers conferred by section 88 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 4531 dated the 15th November, 1976, the Central Government, after consultation with the Employees State Insurance Corporation, hereby exempts the regular employees in Ice-cum-Freezing Plant, Workshops and Shipways, Electronic Section, Processing Section and Gear Section of the Integrated Fisheries Project, Ernakulam under Government of India in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Agriculture) from the operation of the said Act for the period from 5th September, 1977 and inclusive of 30th June, 1978.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The aforesaid factory wherein the employees are employed shall maintain a register showing the names and designations of the exempted employees;

(2) Notwithstanding this exemption, the employees shall continue to receive such benefits under the said Act to which they might have become entitled to on the basis of the contributions paid prior to the date from which exemption granted by this notification operates;

(3) The contributions for the exempted period, if already paid, shall not be refunded;

(4) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;

(5) Any Inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other Official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or

(ii) ascertaining whether register and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act has been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory;

be empowered to—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found inchaige thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises, or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or

(d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory establishment, office or other premises.

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the processing of the application for exemption took time. However, it is certified that the employees of the factories are eligible for exemption. It is also certified that grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

[No. S. 38014/36/76-HI]

का०आ० 1454.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 797, तारीख 26 फरवरी, 1977 के अनुक्रम में, कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श करने के पश्चात् दि फर्टीलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, ट्राम्बे, मुम्बई की उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 5 जनवरी, 1978 से 30 जून, 1978 तक जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, की और अवधि के लिये, छूट देती है ;

2. पूर्वोक्त छूट की शर्तें निम्नलिखित हैं, अर्थात् :—

(1) उक्त कारखाने का नियोजक, उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि' कहा गया है); ऐसी विवरणियां, ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी;

(2) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या निगम का इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी—

(i) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ; या

(ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख का, उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं; या

(iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दिए गए उन फायदों को, जिसके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद में और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं; या

(iv) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के सम्बन्ध में अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबंधों का अनुपालन किया गया था या नहीं;

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा :—

(क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी आवश्यक समझता है, या

(ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसे लेखा, बहियों और अन्य दस्तावेज, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करे और उनकी परीक्षा करने दे, या उन्हें ऐसी जानकारी दें जिसे वे आवश्यक समझते हैं; या

(ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक की, उसके अभिकर्ता या सेवक की, या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना; या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उससे पद्धरण लेना।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस मामले में पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट देनी आवश्यक हो गई है क्योंकि छूट देने के लिए अभ्यावेदन पर कार्रवाई करने में समय लगा। तथापि, यह प्रमाणित किया जाता है कि जिन परिस्थितियों में कारखाने को आरंभ में छूट दी गई थी वे अभी भी विद्यमान हैं और कारखाना छूट का पात्र है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट देने से किसी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

[सं० एस० 38017(4) 76-एच० आई०]

S.O. 1455.—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 797 dated the 26th February, 1977, the Central Government after consultation with the Employees' State Insurance Corporation hereby exempts the Fertilizer Corporation of India Limited Trombay, Bombay from the operation of the said Act for a further period from the 5th January, 1978 upto and inclusive of the 30th June, 1978.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulation, 1950 ;

(2) Any Inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other Official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act has been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory

be empowered to —

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furinsh to him such information as he may consider necessary; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises, or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or

(d) made copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, estabilshment, office or other premises.

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the processing of the application for exemption took time. However, it is certified that the conditions under which the factory was initially granted exemptions till persist and the factory is eligible for exemption. It is also certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of any body adversely.

[No. S. 38017/4/76-HI]

का० आ० 1455.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3456, तारीख 6 सितम्बर, 1976 के अनुक्रम में, कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श करने के पश्चात् सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड प्रेस, रांची को, जो कोल इंडिया लिमिटेड की समनुषंगी है, 26 अक्तूबर, 1977 से 30 जून, 1978 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, को और अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से छूट देती है।

2. पूर्वोक्त छूट की शर्तें निम्नलिखित हैं, अर्थात् :—

(1) उक्त कारखाने का नियोजक, उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अवधि' कहा गया है), ऐसी विवरणियां, ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी;

(2) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या निगम का इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी—

(i) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ; या

(ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख का, उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं; या

(iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दिए गए उन फायदों का, जिसके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद में और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं; या

(iv) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के सम्बन्ध में अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबंधों का अनुपालन किया गया था या नहीं;

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा :—

(क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी आवश्यक समझता है; या

(ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के सन्दाय से संबंधित ऐसे लेखा, बहियों और अन्य दस्तावेज, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दे, या उन्हें ऐसी जानकारी दे जिसे वे आवश्यक समझते हैं; या

(ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक की, उसके अभिकर्ता या सेवक की या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना; या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उससे पद्धरण लेना।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस मामले में पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट देनी आवश्यक हो गई है, क्योंकि छूट के नवीनीकरण के लिए आवेदन देर से प्राप्त हुआ था। तथापि, यह प्रमाणित किया जाता है कि कारखाना छूट का पात्र है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट देने से किसी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[सं० एस० 38014/30/76-एच० आई०]

S.O. 1456.—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 3456 dated the 6th September, 1976, the Central Government after consultation with the Employees' State Insurance Corporation hereby exempts the Central Coalfields Limited Press, Ranchi a subsidiary of Coal India Limited from the operation of the said Act for the further period with effect from the 26th October, 1977 upto and inc'usive of the 30th June, 1978.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations of 1950;

(2) Any Inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other Official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—

(i) verifying the particulars continued in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Emp'oyees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory :—

be empowered to—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises, or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or

(d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other documents maintained in such factory, establishment, office or other premises.

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the application for renewal of exemption was received late. However, it is certified that the factory is eligible for exemption. It is a'so certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

[No. S-38014/30/76-HI]

नई दिल्ली, 8 मई, 1978

का० आ० 1457.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स दि बाम्बे डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज मार्केट, द्वितीय मंजिल, पट्टन रोड, मुम्बई-1, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 जुलाई, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35018(15)/78-पी० एफ II]

New Delhi, the 8th May, 1978

S.O. 1457.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs The Bombay District Central Co-operative Bank Limited, Shree Chhatrapati Shivaji Maharaj Market, Ist Floor, Patton Road, Bombay-1, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment;

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of July, 1976.

[No. S. 3518/15/78-PF. II]

का०आ० 1458.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स लेंटिन चैम्बर्स कन्डोमीनियम, लेटिन चैम्बर्स, दलाल स्ट्रीट फोर्ट, मुम्बई-23, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35018(20)/78-पी०एस० II]

S.O. 1458.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Lentin Chambers Condominium, Lentin Chambers, Dalal Street, Fort, Bombay-23, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment,

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1977.

[No. S-35018 20/78-PF. II]

का०आ० 1459.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स जवाहरलाल राठी, विजियानगरम, विशाखापत्तनम् जिला, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 जनवरी, 1977 को प्रस्तुत हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35019(45)/78-पी० एफ० II]

S.O. 1459.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Jawaharlal Rathi, Vizianagaram, Visakhapatnam District, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment .

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1977.

[No. S-35019/45/78-PF. II]

का०आ० 1460.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स स्वराज टाकीज, तेनाली, जिला गुन्टूर, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 5 मार्च, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35019(430)/77-पी० एफ० II]

S.O. 1460.—Whereas it apears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Swaraj Talkies, Tenali, Guntur District, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment;

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1977.

[No. S-35019/430/77-PF. II]

का०आ० 1461.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स अरुणोदय कम्पनी, डा० अम्बेदकर रोड, पछोड़ा-1, जिला जलगाव, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35018(11)/78-पी०एफ० II]

S.O. 1461.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Arunoday Company, Dr. Ambedkar Road, Pachora-1, District Jalgaon, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment;

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1977.

[No. S-35018/11/78-PF. II]

का०आ० 1462.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स आर्डेक इन्टरनेशनल, 12/ए, कामक स्ट्रीट, कलकत्ता-16, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 अगस्त, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35017(7)/78-पी०एफ० II(i)]

S.O. 1462.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Ardec International, 12/A, Camac Street, Calcutta-16, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment;

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of August, 1977.

[No. S-35017/7/78-PF. II(i)]

का०आ० 1463.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 अगस्त, 1977 से मैसर्स आर्डेक इन्टरनेशनल, 12/ए, कामक स्ट्रीट, कलकत्ता-16, नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस० 35017(7)/78-पी०एफ० II(ii)]

S.O. 1463.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter hereby specifies with effect from the first day of August, 1977 the establishment known as Messrs Ardec International, 12/A, Camac Street, Calcutta-16, for the purposes of the said proviso.

[No. S-35017/7/78-PF. II(ii)]

का०आ० 1464.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स पंजाब राज्य बीज प्रमाणन प्राधिकरण, एस०सी०ओ० 837-38, सेक्टर 22ए, चण्डीगढ़, जिसके अन्तर्गत (1) लुधियाना (2) कोटकपुरा और (3) जलन्धर स्थित इसकी शाखाएं भी हैं, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 जनवरी, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35019(41)/78-पी० एफ० II(i)]

S.O. 1464.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Punjab State Seed Certification Authority, S.C.O. 837-38, Sector 22A, Chandigarh including its branches at (1) Ludhiana, (2) Kotkapura and (3) Jullundur, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment;

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1978.

[No. S-35019/41/78-PF. II(i)]

का०आ० 1465.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 जनवरी, 1978 से मसर्स पंजाब राज्य बीज प्रमाणन प्राधिकरण, एस०सी०ओ० 837-38, सेक्टर 22ए, चण्डीगढ़, जिसके अन्तर्गत (1) लुधियाना (2) कोटकपुरा और (3) जलन्धर स्थित इसकी शाखाएं भी हैं, नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० 35019(41)/78-पी०एफ०II(ii)]

S.O. 1465.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of January, 1978 the establishment known as Messrs Punjab State Seed Certification Authority, S.C.O. 837, Sector 22A, Chandigarh including its branches at (1) Ludhiana, (2) Kotkapura and (3) Jullundur, for the purposes of the said proviso.

[No. S-35019/41/78-PF. II(ii)]

का०आ० 1466.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स निकी ताशा इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड, ई-1 और 2, साउथ एक्सटेंशन, भाग-2, नई दिल्ली-49 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 जुलाई, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019(65)/78-पी०एफ० II]

S.O. 1466.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Niky Tasha India (Private) Limited, E-I and 2 South Extension, Part-II, New Delhi-49, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment;

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of July, 1977.

[No. S-35019/65/78-PF. II]

का०आ० 1467.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सारंग स्टील फैब्रिकेटर्स पी०ए० 62 उद्यमबाग बेलगाम, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 दिसम्बर, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019 (35)/78-पी०एफ० II]

S.O. 1467.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sarang Steel Fabricators, P. L. 62, Udyambag, Belgaum, have agreed that the provision of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of December, 1977.

[No. S. 35019/35/78-PF. II]

का०आ० 1468.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स अरुण एण्ड राजीव (प्राइवेट) लिमिटेड एस०सी०ओ० सं० 14, सेक्टर 17-ई, चण्डीगढ़, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 जनवरी, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35019(37)/78-पी०एफ० II]

S.O. 1468.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Arun and Rajiv (Private) Limited, S.C.O. No. 14, Sector 17E, Chandigarh, have agreed that the provision of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1978.

[No. S-35019/37/78-PF. II]

का०आ० 1469.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स पापुलर रेस्ट्रा, माडीकेरी, कुर्ग, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 मार्च, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35019 (67)/78-पी०एफ० II]

S.O. 1469.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Popular Restaurant, Madikeri, Coorg, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of March, 1978.

[No. S-35019/67/78-PF. II]

का०आ० 1470.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स पीनट प्रोडक्टस, तन्ना हाउस, तीसरी मंजिल, 11-ए, नथालाल डी पारेख मार्ग, मुम्बई 39, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 नवम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35018(16)/78-पी०एफ० II(i)]

S.O. 1470.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Peanut Products Tanna House, 2nd Floor, 11-A Nathalal D. Parekh Marg, Bombay-39, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (10 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of November, 1976.

[No. S-35018/16/78-PF. II (i)]

का०आ० 1471.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 नवम्बर, 1976 से मैसर्स पीनट प्रोडक्टस, तन्ना हाउस, तीसरी मंजिल 11-ए, नथालाल डी पारेख मार्ग, मुम्बई-39, नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस०-35018(16)/78-पी० एफ० II(ii)]

S.O. 1471.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day

of November, 1976 the establishment known as Messrs Peanut Products, Tanna House, 2nd Floor, 11-A Nathalal D. Parekh Marg, Bombay-39 for the purposes of the said proviso.

[No. S-35018/16/78-PF. II (ii)]

का०आ० 1472.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स जैम ज्यलरी एण्ड पेस्टो-केम (प्राइवेट) लिमिटेड, 904, रीजेन्ट चैम्बर्स, नरिमन प्वाइंट, मुम्बई-21, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 30 अप्रैल, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[स० एस० 35018(17)/78-पी एफ० II]

S.O. 1472.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Gem Jewellery and Peasto-Chem (Private) Limited, 904, Regent Chambers, Nariman Point, Bombay-21, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of April, 1977.

[No. S-35018/17/78-PF. II]

का०आ० 1473.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एल०एम० इंजीनियरिंग कम्पनी, 81, नीलगंज रोड, अगरपारा, 24 परगना, पश्चिम बंगाल, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 जून, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[स० एस० 35017(8)/78-पी०एफ० II]

S.O. 1473.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. L. M. Engineering Company, 81, Nilganj Road, Agarpara, 24-Parganas, West Bengal have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of June, 1977.

[No. S-35017/8/78-PF. II]

का०आ० 1474.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स फैब फोर्ज इंजीनियर्स, 23, फीडर रोड, कलकत्ता-57, जिसमें बी/2, बांन-हुगली इण्डस्ट्रियल एस्टेट, कलकत्ता-35 स्थित उसकी शाखा भी सम्मिलित है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[स० एस० 35017(9)/78-पी०एफ० II]

S.O. 1474.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Fab-Forge Engineers, 23, Feeder Road, Calcutta-57 including its branch at B/2, Bon-Hooghly Industrial Estate Calcutta-35, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1977.

[No. S-35017/9/78-PF. II]

का०आ० 1475.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स दि गुहया अगस्थेश्वर सर्विस कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सिद्दापुर, साउथ कुर्ग, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है

यह अधिसूचना 1 मार्च, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० स० 35019(66)/78-पी०एफ II]

S.O. 1475.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs The Guhya Agastheswara Service Co-operative Society Limited, Siddapur, South Coorg, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of March, 1978.

[No. S-35019/66/78-PF. II]

का०आ० 1476.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 3871 तारीख 23 नवम्बर, 1977 के अनुसरण मे, कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श करने के पश्चात् इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (परिष्करणी और पाइप लाइन खण्ड) गोहाटी परिष्करणी, गोहाटी (जिसे पहले इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड, गोहाटी कहा जाता था) को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 1 जनवरी, 1978 से 30 जून, 1978 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, की और अवधि तक छूट देती है।

2. पूर्वोक्त छूट की शर्तें निम्नलिखित है, अर्थात :--

(1) उक्त कारखाने का नियोजक, उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था (जिसे इसमे इसके पश्चात् 'उक्त अवधि' कहा गया है), ऐसी विवरणियां, ऐसे प्ररूप मे और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी;

(2) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या निगम का इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी--

(1) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ; या

(2) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख का, उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं; या

(3) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दिए गए उन फायदो को, जिसके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद मे और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नही; या

(4) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के सम्बन्ध में अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्ही उपबन्धों का अनुपालन किया गया था या नही;

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा :--

(क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी आवश्यक समझता है; या

(ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर मे किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियो के नियोजन और मजदूरी के सन्दाय से संबंधित ऐसे लेखा बहियां और अन्य दस्तावेज, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करे और उनकी परीक्षा करने दें, या उन्हें ऐसी जानकारी दे जिसे वे आवश्यक समझते है; या

(ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक की, उसके अभिकर्ता या सेवक की या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर मे पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे मे उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना, या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उससे पदधारण लेना।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस मामले में पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट देनी आवश्यक हो गयी है क्योंकि छूट के लिए प्राप्त आवेदन पत्र की कार्रवाई पर समय लगा। तथापि यह प्रमाणित किया जाता है कि जिन परिस्थितियो मे कारखाने को आरंभ में छूट दी गयी थी वे अभी भी विद्यमान है और कारखाना छूट का पात्र है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट देने से किसी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ेगा।

[सं० एस० 38014/46/76-एच०आई०]

एस० एस० सहस्रनामन, उप सचिव

S.O. 1476.—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 3871 dated the 23rd November, 1977, the Central Government after consultation with the Employees State Insurance Corporation hereby exempts the Indian Oil Corporation Limited (Refineries and Pipelines Division) Gauhati Refinery, Gauhati (previously known as Indian Refineries Limited Gauhati) from the operation of the said Act for a further period with effect from the 1st January, 1978 upto and inclusive of the 30th June, 1978.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations of 1950;

2. Any Inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other Official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Rerulations, 1950 for the said period; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act has been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory;

be empowered to—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant or any person found in such factory, establishment, office or other promises, or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or

(b) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the processing of the application for exemption took time. However, it is certified that the conditions under which the factory was initially granted exemption still persist and the factory is eligible for exemption. It is also certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

[No. S. 38014/46/76-HI]
S. S. SAHASRANAMAN, Dy. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 3 मार्च, 1978

का०आ० 1477.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में बैंक ऑफ बड़ौदा, अहमदाबाद, के प्रबन्ध तंत्र से सम्बद्ध नियोजक और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री आर०सी० इसरानी होंगे, जिनका मुख्यालय अहमदाबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या बैंक आफ बड़ौदा, अहमदाबाद के प्रबन्ध तंत्र की बैंक की कपड़वंज शाखा के गोदाम कीपर, श्री अनिल पी० पारिख, की सेवा की 30-11-73 से समाप्त करने की कार्रवाई न्यायोचित है? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल-12012/203/76-डी-2ए]

ORDER

New Delhi, the 3rd March, 1978

S.O. 1477.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of the Bank of Baroda, Ahmedabad and their workman in respect of matters specified in the schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A read with clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal Presiding Officer of which shall be Shri R. C. Israni, with headquarters at Ahmedabad and refers the said dispute to the Central Government Industrial Tribunal, Ahmedabad.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of the Bank of Baroda in terminating the services of Shri Anil P. Parikh, Godownkeeper, Kapadwanj Branch of the Bank with effect from 30-11-1973 is justified? If not to what relief is the workman entitled ?"

[F. No. L-12012/203/76-D.II.A]

New Delhi, the 8th May, 1978

S.O. 1478.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal New Delhi in the industrial disputes between the employers in relation to the management of Dena Bank, Delhi Region, and their workmen over the transfer of S/Shri Ashok Kumar and M. M. Sharma, Clerks-cum-Cashiers which was received by the Central Government on 3-5-1978.

BEFORE SHRI MAHESH CHANDRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NEW DELHI

LD. No. 151 of 1977

BETWEEN

The General Secretary, Dena Bank Workers Organisation, 5239, Ajmeri Gate, Delhi. ...Petitioner.

Versus

The Regional Manager, Dena Bank, 26-A, Barakhamba Road, Akashdeep, New Delhi. ...Respondent.

PRESENT :

Shri C. L. Bhardwaj—for the workmen.
Shri R. C. Pathak, Advocate—for the Management.

AWARD

The Central Government as appropriate Government made a reference u/s 10 of the I.D. Act, 1947 vide its order No. L. 12012/84/74/LRIII dated the 20th December, 1974 to Industrial Tribunal, Delhi :

'Is the management of Dena Bank, Delhi Region New Delhi, justified in transferring S/Shri Ashok Kumar and M. M. Sharma, Clerk-cum-Cashiers and Organising Secretary and Vice President respectively of Dena Bank Workers Organisation, from Okhla to Wazirpur and from Darya Ganj to Chhaterpur respectively ? If not, to what relief are they entitled ?

2. After usual notices were served upon the workman and the Bank a statement of claim was filed on behalf of the workmen and a written statement thereto was also filed. Thereafter a replication was got filed and following issues were framed by Industrial Tribunal, Delhi vide his order dated 29-5-1975 :

1. Whether there is an Industrial Dispute between the parties, within the meaning of Section 2(k) of the I.D. Act.

2. As in the terms of reference.

3. The workman did not produce any evidence. Therefore the evidence of the workmen was closed vide order dated 14-8-1975 and the case was adjourned for the evidence of the Management, but the said order was set aside and the case was fixed for evidence of the workmen. In the meanwhile this reference was transferred to this Tribunal by the appropriate Government and after the case was registered usual notices was sent to the parties and case was fixed for evidence to 23rd November, 1977. Thereafter an adjournment was requested for a compromise and on the 27th January, 1978 Shri R. C. Pathak, counsel for the Bank had stated that Shri Ashok Kumar had been transferred on his request and the reference qua him is no longer a subsisting dispute and in pursuance thereof statement of Shri Ashok Kumar was recorded on that day wherein it was stated by him that 'I have been transferred as per request and there is no dispute subsisting between me and Bank on this matter.' Thereafter Shri R. C. Pathak came forward with a statement that 'the Bank is prepared to transfer Shri M. M. Sharma back to his original place or to any other place he would request. Let him file an application in this behalf.' Shri R. C. Pathak then made a statement on 8-2-1978 that the 'respondent has already been transferred to Darya Ganj Branch of Dena Bank as per request by the workmen,' and thereupon statement of Shri M. M. Sharma

was also recorded on 10th February, 1978 in which Shri Sharma stated that 'I have taken over charge in the new place of posting'. In these circumstances it was submitted by Shri R. C. Pathak, counsel for the Bank that the workmen having been transferred to the place of choice the dispute does not subsist any longer and a formal application in this behalf was filed and a reply was filed on behalf of the workmen.

4. I have heard Shri C. L. Bhardwaj for the workmen and Shri R. C. Pathak for the Bank and have given my considered thought to the matter before me and I have come to the finding that considering the order of reference, it cannot be said that any Industrial Dispute subsists between the workmen and the Management in the instant matter. As the order of reference would show the reference was regarding the justification of transfer of Shri Ashok Kumar and M. M. Sharma and the consequent relief they were entitled to. However after the reference was made the Management has re-transferred Shri M. M. Sharma to Darya Ganj Branch itself while Shri Ashok Kumar has been transferred to the Branch of his choice and consequently it would follow that the workmen were not entitled to any further relief and hence it cannot be said that any dispute subsists between the parties. I hold accordingly that no Industrial Disputes subsists between the parties as brought out by the order of reference and accordingly a no dispute award is made in the matter. However I would like to make it clear here that if these workmen or any one of them are inclined to claim any money advantage out of any harassment resulting from the original transfer it is not covered within the scope of reference and therefore it cannot be subject matter of determination in this reference. This award would not therefore prejudically effect the right of the workmen in this behalf.

Parties would bear their own costs.

Dated : 15th March, 1978.

MAHESH CHANDRA, Presiding Officer.

[F. No. L-12012/84/74-LRIII]

S.O. 1479.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal New Delhi in the industrial dispute between the employers in relation to the management of State Bank of India, Jaipur and their workmen over the termination of the services of Shri N. L. Sharma, Clerk M. I. Road Branch, Jaipur which was received by the Central Government on the 3-5-78.

BEFORE SHRI MAHESH CHANDRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NEW DELHI

I.D. No. 172 of 1977

BETWEEN

Shri N. L. Sharma C/o. Rawal Tailors, Opposite Railway Station, Power House Road, Jaipur-6.

—Petitioner.

Versus

The Branch Manager, State Bank of India, Station Road Jaipur. —Respondent

PRESENT :

Shri N. L. Sharma, the concerned workman.
Shri S. Mishra, Asstt. Law Officer for the Bank.

AWARD

Hhe Central Government as appropriate Government made a reference u/s 10 of the Industrial Dispute Act, 1957 to this Tribunal in the following terms vide its order No. L-12012/185/76-D. II. A dated the 20th July, 1977 :

Whether the action of the management of the State Bank of India in terminating the services of Shri N. L. Sharma, Clerk, M. I. Road, Jaipur Branch of the Bank with effect from 31-8-74 is legal and justified ? If not to what relief is the workman entitled ?

2. On receipt of reference usual notice was sent to the parties and a statement of claim was filed by the workman but before any written statement was filed on behalf of the Bank there was a move for compromise between the parties and finally a compromise has been arrived at between the parties which has been recorded vide statements of Shri S. Mishra, Asstt. Law Officer of the State Bank of India and Shri N. L. Sharma, the workman on 25-2-1978. The said statement reads as follows :

The parties have arrived at a settlement. The respondent agrees to employ Shri N. L. Sharma on substantive basis and the workman gives up his claim for arrears if any. So award may be made directing that the workman shall be appointed by the State Bank of India at Jaipur on substantive basis without any period of probation w.e.f. the 15th of March, 1978 on the production of a medical fitness certificate from the local workman would not be entitled to arrears of wages or any other benefit of previous service. Parties be left to bear their costs.

3. From the perusal of the above statements I find that the settlement is for the benefit of the parties and as such it would be appropriate to accept it and register it. Accordingly the statement is registered.

4. In pursuance of the settlement as incorporated in the statements recorded above, the State Bank of India is directed to appoint on substantive basis without any period of probation Shri N. L. Sharma as a clerk in State Bank of India at Jaipur w.e.f. 15th March, 1978. It shall be the responsibility of Shri N. L. Sharma to produce a medical fitness certificate from the Local Medical Jurist. It is also awarded that the workman would not be entitled to arrears of wages or any other benefit of previous service. Parties are left to bear their own costs.

Dated : 2nd March, 1978

MAHESH CHANDRA, Presiding Officer

[F. No. L-12012/185/76-D II A]

R. P. NARULA, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 3 मई, 1978

का०आ० 1480.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसूर सीमेंटस लिमिटेड, समासन्दरा के प्रबन्ध तंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अत: अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री जी० एस० भगवत होंगे, जिनका मुख्यालय बंगलौर में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या मैसूर सीमेंट्स एम्प्लाइज एसोसियेशन की मैसूर सीमेंट लि० की खानों में (क) लाइन स्टोन ढोने और तोड़ने के लिए सामान्य कार्यभार का पुनर्नियतन (ख) सामान्य कार्यभार ऊपर दर्शित (क) के अनुसार न्यूनतम गरंटेड मजदूरी का नियतन की मांगें न्यायोचित है ? यदि नहीं तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष के अधिकारी है और किस तारीख से ?

[सं० एल० 29011/11/77-डी० थ्री बी०]

ORDER

New Delhi, the 3rd May, 1978

S.O. 1480.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Mysore Cements Ltd., Ammasandra and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri G. S. Bhagwat shall be the Presiding Officer, with headquarters at Bangalore and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the demands of the Mysore Cement Employees' Association for (a) Re-fixation of the norms of workloads for breaking and loading of Limestone and (b) fixation of Minimum guaranteed wages, based on the norms of the work-load as per (a) above, in the quarries of Mysore Cements Ltd. are justified ? If not, to what relief are the workmen entitled and from which date ?"

[No. L-29011/11/77-D. III. B.]

आदेश

का० आ० 1481.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में श्री कोडानडारामा बारयटस माईन, सनखावाराम, गांव विन्जामुर (पोस्ट) उदयगिरी तालुक, नैलोर जिला, के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कमकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री के० पी० नारायणा राव होंगे, जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या श्री कोडानडारामा बारयटस माइन, सनखावाराम, गांव, उदयगिरी तालुक, नैलोर जिला, आन्ध्र प्रदेश, प्रबंधतंत्र की श्री नैलामकांडा बालाराजाहि, मजदूर को 23-5-77 से रोजगार देने से इंकार करना और अन्त में उसकी सेवाओं को 11-6-77 से समाप्त करने की कार्रवाई न्यायोचित थी ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस उक्त अनुतोष का अधिकारी है ?

[सं० एल० 29012/28/77 डी०थ्री०बी०]

S.O. 1481.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Management of Shri Kodandarama Barytes Mine, Sankhavaram, Village, Vinjamur (Post) Udayagiri Taluq, Nellore Distt. and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with Shri K. P. Narayana Rao as Presiding Officer with Headquarters at Hyderabad and refers the said dispute for adjudication to the said Industrial Tribunal.

THE SCHEDULE

"Whether the action of the Management of Shri Kodandarama Barytes Mine Sankhavaram Village, Udayagiri Taluq, Nellore District, Andhra Pradesh in refusing employment to Shri Bellamkonda Balaramaiah, Mazdoor w.e.f. 23-5-77 and finally terminating his services w.e.f. 11-6-77 was justified ? If not, to what relief the said workman is entitled ?"

[No. L-29012/28/77-D. III. B.]

आदेश

नई दिल्ली, 5 मई, 1978

का० आ० 1482.—श्री रामजीदास रामरिछपाल, खान स्वामी, मोरक और श्री राम भगत रामजीदास, खान स्वामी, मोरक से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कमकारों, जिनका प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय मजदूर संघ रामगंज मण्डी करती है, के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और उक्त नियोजक और कर्मकार उक्त औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10क की उपधारा (1) के अनुसरण में एक लिखित करार द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा माध्यस्थम् के लिए निर्दिष्ट किए जाने के लिए सहमत हो गए हैं और उक्त करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को उपलब्ध करा दी गई है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क की उपधारा (3) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त करार को प्रकाशित करती है ।

करार

(औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10क के अधीन)

निम्नलिखित के मध्य

पक्षकारों के नाम

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले : श्री रामभगत रामजीदास, खान स्वामी, मोरक स्टेशन, जिला कोटा (राजस्थान) ।

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले : श्री स्वादिम कुमार शर्मा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मजदूर संघ, रामगंजमण्डी । श्री राम गोपाल गुप्त, कार्यालय सचिव, राष्ट्रीय मजदूर संघ, रामगंज मण्डी, कोटा ।

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित विवाद को श्री श्याम कृष्ण, प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), अजमेर के माध्यस्थम् के लिए निर्दिष्ट करने का करार किया गया है ।

"क्या रामगंज मंडी, कोटा के राष्ट्रीय मजदूर संघ की, (i) श्री राम भगत रामजीदास, और (ii) श्री रामजीदास रामरिछपाल, क्रमशः पीपाकुड़ी और अस्कट पत्थर खान के खान स्वामियों द्वारा नियोजित संगतराशों (स्टोन कटर्स) को मजदूरी का अतिरिक्त संदाय करने की मांग न्यायोचित है ? यदि हां, तो कर्मकार किस अनुतोष के और किस तारीख से हकदार हैं ?

विवाद द्वारा प्रभावित होने वाले कर्मकारों का कुल संख्या लगभग 200 है ।

हम यह भी करार करते हैं कि मध्यस्थ का विनिश्चय हम पर आबद्धकर होगा ।

मध्यस्थ अपना पंचाट, समुचित सरकार द्वारा इस करार के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर या इतने और समय के भीतर जो हमारे बीच पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ाया जाए, देगा । यदि ऊपर वर्णित अवधि के भीतर पंचाट नहीं दिया जाता है तो माध्यस्थम् के लिए निर्देश स्वतः रद्द हो जाएगा और हम नए मध्यस्थम् के लिए बातचीत करने को स्वतंत्र होंगे ।

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले :	प्रबन्ध तन्त्र का प्रतिनिधित्व करने वाले
1. ह० (स्वदिन कुमार शर्मा)	ह० (राम भगत रामजीदास)
2. ह० (रामगोपाल गुप्त)	

साक्षी :

1. ह० (एच सी० मूल चन्दानी)
   मार्फत आर एल सी (सी), अजमेर
2. ह० के आई थामस
   मार्फत आर एल सी (सी), अजमेर

[सं० एल 29011/13/77/डी-III बी]
जगदीश प्रसाद, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 5th May, 1978

S.O. 1482.—Whereas an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Shri Ramjidas Ramrichpal, Mine Owner, Morak and Shri Rambhagat Ramjidas, Mine Owner, Morak and their workmen represented by Rashtriya Mazdoor Sangh Ramganjmandi.

And whereas the said employers and workmen have, by a written agreement in pursuance of the provisions of the sub-section (1) of section 10-A of the Industrial Disputes Act, 1947 agreed to refer the said dispute to arbitration by the persons specified therein and a copy of the said agreement has been made available to the Central Government.

Now, therefore, in pursuance of sub-section (3) of section 10-A of the said Act, the Central Government hereby publishes the said Agreement.

AGREEMENT

(Under Section 10-A of the Industrial Disputes Act, 1947)

BETWEEN

Name of the Parties :

Representing Employers : Sh. Ram Bhagat Ramjidas, Mine Owner, Morak Station, Distt. Kota (Rajasthan).

Representing workmen : Sh. Swadin Kumar Sharma, President, Rashtriya Mazdoor Sangh, Ramganjmandi.
Sh. Ram Gopal Gupta, Office Secretary, Rashtriya Mazdoor Sangh, Ramganjmandi, Kota.

It is hereby agreed between the parties to refer the following dispute to the Arbitration of Shri Shyam Krishna, Regional Labour Commissioner (Central), Ajmer.

"Whether the demand of Rashtriya Mazdoor Sangh of Ramganjmandi, Kota, asking for additional payment of Wages to the Stone-cutter employed by (i) Shri Ram Bhagat Ramjidas, and (ii) Shri Ramji Das Ramrichpal, Mine Owners of Pipakuri and Askat Stone Mines respectively is justified. If so to what relief and from what date the workmen are entitled to ?"

Total number of workmen affected by the dispute is 200 approximately.

We further agree that the decision of the arbitrator be binding on us.

The Arbitrator shall make his award within a period of three months from the date of publication of this agreement in the Official Gazette by the appropriate Government or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing. In case the award is not made within the period aforementioned, the reference to arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitration.

Representing workmen :	Representing Management
1. Sd/- (Swadin Kumar Sharma)	1. Sd/- (Ram Bhagat Ramjidas).
2. Sd/- (Ram Gopal Gupta)	

Witnesses :

1. Sd/- (H.C. Moolchandanney) C/O RLC(C), Ajmer	2. Sd/- (K.I. Thomas) C/O RLC(C), Ajmer.

Ajmer,
1st Nov. 1977

[No. L-29011/13/77-D.III.B]

S.O. 1483.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Jabalpur (M.P.), in the industrial dispute between the employers in relation to the Management of Manganese Ore (India) Limited, Nagpur and their workmen, which was received by the Central Government on the 2nd May, 1978.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M. P.)

Case No. CGIT/LC(R) (8) of 1977

PARTIES :

Employers in relation to the Management of Manganese Ore (India) Limited, Nagpur and their Workmen represented through the Secretary, Samyukta Khadan Mazdoor Sangh (AITUC), Mazdoor Bhawan, Distt. Balaghat (M. P.).

APPEARANCES :

For Management—Shri P. S. Nair, Advocate.

For Workmen—Shri P. K. Thakur, Advocate.

INDUSTRY : Manganese Ore DISTRICT : Balaghat (M.P.)

Dated, the 20th April, 1978

AWARD

This is a reference made by the Government of India in the Ministry of Labour vide it's order No. L-27012/4/74-IR. IV/dated 25/26th April, 1977 for the adjudication of the following industrial dispute by this Tribunal :—

"Whether the management of Manganese Ore (India) Limited, Nagpur in relation to their Balaghat Manganese Mines, are justified in dismissing Sarvashri Bapu s/o Shri Goma, Ganga Prasad s/o Shri Manik, Ramji s/o Shri Chandan, and Gulab, Markam, all workmen in Balaghat Manganese Mine from service with effect from different dates during August and September, 1972 ? If not, to what relief are these workmen entitled ?"

2. It is not disputed that the services of the aforesaid 4 workers were terminated after domestic enquiry for indiscipline. Samyukta Khadan Mazdoor Sangh Union affiliated to AITUC raised the dispute; conciliation failed and this reference, for which the Government had first refused, was ultimately made by it to this Tribunal for adjudication of this dispute.

3. The Management has raised some important pleas against the validity of the reference which are decided as

preliminary issues. The Management's plea is that S.K.M.S. Union never existed in Bharwoli Mines. No industrial dispute could be sponsored by it. The case of the Union is that it existed as a minority union and the terminated workmen were its members.

4. The constitution of the Union goes to show that it is a general union which enrolls workmen not only of Manganese Mines but of Coal and other industries as well. There is no evidence that this general union has any existence membership strength in Bharwoli Mines. It is not proved that even the workmen whose cause has been so espoused by this S.K.M.S. Union are its members. Since the reference was made at the instance of this Union a presumption was in favour of its representatives capacity. But that presumption was amply rebutted by the evidence produced by the Management which remains wholly unrebutted as no witness was examined on behalf of the Union.

5. Shri M. K. Sarkar (M. W. 1) stated on oath that out of the total strength of 2870 workers in Bharwoli Mines his Union, which is known as Rashtriya Manganese Mazdoor Sangh affiliated to INTUC, has the membership strength of 2812. The remaining workers do not belong to any Union. They have entered into an arrangement with the Management that the membership fee is directly realized from these workers by the Management and is credited to Syndicate Bank in the Union's account. That Union is the registered and recognised Union and Shri Sarkar is the General Secretary thereof. He has asserted emphatically that S.K.M.S. Union did not at any time exist in Bharwoli Mines and had no membership. In fact it was Rashtriya Manganese Mazdoor Sangh of which these workmen were members that had sponsored their cause of and had ultimately come to terms with the Management by accepting some ex gratia payment for these wokers because under no circumstances the Management was prepared for taking them back in service on account of their most indisciplined behaviour.

6. Shri K.A.N. Tripathi, Personnel Officer, now in Tirodi Manganese Mines (W. W. 2) was once in Bharwoli Mines from 16th November, 1971 to 7th December, 1976. He has also denied existence of S.K.M.S. Union at Bharwoli Mines. It did not operate even as minority Union. It never raised any dispute before the Managements during his stay. This witness stated that in the year 1972, 1974 and 1976 during his stay he had conducted three elections of Works Committee. According to Rule 41 of Industrial Disputes (Central) Rules he notified that if any Union existed, it should furnish particulars but no such Union ever came forward to supply any such particulars in response to that notice except the aforesaid INTUC Union. The evidence of both the witnesses clearly rebuts the presumption that would have arisen from the reference being made at the instance of S.K.M.S. Union that it must be having some representative capacity. These witnesses prove to the hilt that S.K.M.S. Union does not exist even as minority Union in Bharwoli Mines and it has not only no membership but even the concerned workmen are not proved to have become its members.

7. In Workmen of Dharampal Premchand Saugandhi Vs. Dharampal Premchand Saugandhi (3 SCLJ 1943) it was clearly observed at page 1949 that a general Union of the industry can represent the cause of the workmen of an establishment if it has some membership in that establishment and if the workmen of that establishment have no Union of their own. The words of the Supreme Court may be quoted as follows :—

> "But in a given case it is conceivable that the Workmen of an establishment have no Union of their own and some or all of them joined the Union of another establishment belonging to the same Industry. In such a case if the said Union takes up the cause of the workmen working in an Establishment which has no Union of its own, it would be unreasonable to hold that the dispute does not become an Industrial dispute, because the Union which has sponsored it is not the Union exclusively of the workmen, working in the establishment concerned....." Industry has been defined by Section 2 (j) of the Act and it seems to us that in some cases the union of the workmen working in one Industry may be competent to raise a dispute about the wrongful dismissal of an employee engaged in an establishment belonging to the same industry where workmen in such an establishment have no Union of their own and an appreciable number of such workmen had joined other Union before their dismissal."

In the present case both the elements underlined above are absent. Neither it is proved that an appreciable number of workmen had joined S.K.M.S. Union before their dismissal nor it is a fact that there is no Union of the workmen of Bharwoli Mines. On the contrary it is established by the evidence of Shri Sarkar that a very large Union representing almost whole lot of the workmen does operate in that establishment. Under the circumstances it is held that the individual dispute of the dismissal of the aforesaid persons could not be converted into an Industrial Dispute by an outside Union coming to their rescue when that union has no legs to stand in that establishment and the workmen of that establishment have their own largely represented Union. As sponsoring of the individual dispute by S.K.M.S. Union did not give it a character of Industrial Dispute the reference could not lie and therefore, the order of reference does not give any jurisdiction to this Tribunal to adjudicate upon the dispute so referred by the Government of India.

8. As is evident from the evidence of Shri Sarkar (M.W. 1) this largely represented INTUC Union of Bharwoli Mines took up the question of these workmen with the Management and they had come to a settlement under which some ex gratia payment was accepted. The settlement stands unless that is set aside. No Industrial Dispute could be raised till if exists and on that account also the reference is not valid.

9. One of the workmen namely Ganga Prasad alongwith four others filed a Civil Suit for declaration that the order of termination of his service on the ground of conduct subversive of discipline was void and ineffective. This Civil Suit No. 16A of 1973 was decided by the II Civil Judge, Class II, Balaghat on 12-12-1973 and the suit was dismissed. Under issue Nos. 1 and 3 it was specifically decided that sufficient opportunity to make a statement cross-examination of witnesses and to adduce evidence was given to the Plaintiffs including Ganga Prasad. It is a question whether after the decision of the Civil Court in the matter this Tribunal will be competent to give any findings contrary to that decision. The other points need no discussion in view of the finding against the validity of reference given above. It is thus held that the reference is not valid and maintainable. The Award is given accordingly.

S. N. JOHRI, Presiding Officer

dated : 20-4-1978.

[No. L-27012/4/74-CR IV/D III B]
JAGDISH PRASAD, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 मई, 1978

का० आ० 1484—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ङ) के उपखण्ड (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 3662 तारीख 4 नवम्बर, 1977 द्वारा किसी तेल क्षेत्र में सेवा को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 22 नवम्बर, 1977 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था ;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है ;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ङ) के उपखण्ड (6) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 22 मई, 1978 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है ।

[सं० एस०-11017/4/78-डी० 1(ए)]

New Delhi, the 6th May, 1978

S.O. 1484.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required, had in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S. O. 3662 dated the 4th November, 1977 the services in any Oil field to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months from the 22nd November, 1977;

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a further period of six months from the 22nd May, 1978.

[No. S. 11017/4/78/DI(A)]

नई दिल्ली, 8 मई, 1978

का० आ० 1485—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित मे ऐसा करना अपेक्षित था औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उप-खण्ड (6) के उपबन्धों के अनुसरण मे भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 3939 तारीख 26 नवम्बर, 1977 द्वारा बैंक नोट प्रेस, देवास में सेवा को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 26 नवम्बर, 1977 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था ।

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छ. मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है ;

अतः, अब, औद्योगिक अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (6) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनो को 26 मई, 1978 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा सेवा घोषित करती है ।

[सं० एस०-11017/7/78-डी० 1(ए)]

New Delhi, the 8th May, 1978

S.O. 1485.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required, had in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of Government of India in the Ministry of Labour No. S. O. 3939 dated the 26th November, 1977 the service in the Bank Note Press, Dewas, to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the 26th November, 1977;

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a further period of six months from the 26th May, 1978.

[No. S. 11017/7/78/DI(A)]

का० आ० 1486—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2, के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (1) के उपबन्धों के अनुसरण में, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 3873 तारीख 17 नवम्बर, 1977 द्वारा किसी लोह अयस्क खान उद्योग मे सेवा को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 18 नवम्बर, 1977 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित मे उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढाया जाना अपेक्षित है ,

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त उद्योग को प्रयोजनो के लिए 18 मई, 1978 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है ।

[स०एस-11017/6/78-डी० 1(ए)]

एल० के० नारायणन्, डैस्क अधिकारी

S.O. 1486.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required, had in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S. O. 3873 dated the 17th November, 1977, the Iron Ore Mining Industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months from the 26th November, 1977 ;

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest required the extension of the said period by a further period of six months ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a further perod of six months from the 18th May, 1978.

[No. S. 11017/6/78/DI(A)]

L. K. NARAYANAN, Desk Officer.

New Delhi, the 3rd May, 1978

S.O. 1487.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Bombay in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Bombay Licensed Measures Limited, Bombay and their workmen which was received by the Central Government on the 2nd May, 1978.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

Reference No. CGIT-2/15 of 1976

Employers in Relation to the Management of Messrs Bombay Licensed Measurers Limited, Mackinnon Building, Ballard Estate, Bombay-400038.

AND

Their workmen Shri Alfred T. Martyris, Junior Measurer.

APPEARANCES :

For the Employers—1. Shri S. V. Mokashi, Labour Adviser. 2. Shri C. V. Pavaskar, Additional Labour Adviser 3. Shri D. G. Shinde, Office Assistant.

For the workman—Shri Alfred T. Martyris, (workman in person).

INDUSTRY : Ports and Docks STATE : Maharashtra

Bombay, dated the 10th April, 1978

AWARD

1. The Government of India, in the Ministry of Labour acting under the powers conferred upon it under Section 10(1) (d) of the Industrial Disputes Act, 14 of 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication by order No. L-31012(8)/76-D-IV(A) dated 11-11-1976.

2. Messrs Licensed Measurers Ltd., Bombay has filed written statement on 7-1-1977 stating that their company carries on business of measuring and weighing cargo, issuing certificates of measurement or weighment relating to the goods imported or exported from the Port of Bombay. The Steam Ship companies or the exporters usually ask the company to depute Measurers to execute their work of measurement in respect of the cargoes to the exported and to furnish certificates to that effect. On the basis of this certificate issued by the company the Exporter is charged freight by the Shipping companies. The workman herein Shri Martyris was working in this company as a Junior measurer since 17-5-1972 in the company's office at Indira Dock. On 30-5-1975 the workman was deputed by the company to take measurement of a frozen cargo of shrimps lying at 19, Indira Docks from 5.30 P.M. and thereafter from 11.30 P.M. in the third shift as per the request received from M/s. Patvolk, Agents of S. S. Hoegh Orchid. After taking the measurements of the 521 cartons the workman issued three certificates to the Shipper Nos. T/144696/3243, T/144697/3242 and T/144698/3244 under date 30-5-1975. As the Superintendent of the company suspected the correctness of the measurement disclosed in these certificates, he ordered a Senior Measurer to take fresh measurements on 31-5-1975. As per the revised certificate issued by the Senior measurer on 31-5-1975 the cargo was weighing 5-1/2 metric tonnes more than what was shown in the certificate issued by the workman herein on the previous day. On the basis of the revised measurement submitted on 31-5-1975, the shipper paid the charges. For this misconduct the company issued a charge-memo. to the workman herein. An enquiry was held into this misconduct as per rules. The workman participated in the enquiry. The Enquiry Officer found the workman guilty of dishonesty and gross-negligence in the performances of his duties. On the basis of this report the company discharged the workman from their service. The management also submits that the work entrusted to the Measurer being of a very responsible nature, they do not want to continue to employ him after losing confidence in his honesty and integrity.

3. The workman filed statement of claim stating that the finding of the Enquiry Officer is not warranted by the material placed on the record. He also submits that the Enquiry is vitiated by several irregularities. He prays that he may be reinstated in service with full back wages.

4. On 3-4-1978 the parties appeared before this Court and filed a Memo. of compromise praying this Tribunal to pass an award in terms thereof. As the Tribunal was not sitting on that day the same was called on 10-4-1978 on which date the workman was present in person while the company was represented by Shri Shinde, Office Assistant. As the parties admitted the terms of compromise the same was recorded. In terms of compromise Rs. 1,579.45 representing the company's share of Provident Fund and another sum of Rs. 1,540 as ex gratia payment, were paid by cheque. The workman accepted the above payments in full satisfaction of all his claims against the management. On carefully going through the material placed before me I am satisfied that the compromise is in the interests of the workman.

5. In view of the joint request made by both the parties an award in terms of the compromise is passed. Copy of the compromise Memo. attached hereto may be read as part of this Award.

P. RAMAKRISHNA, Presiding Officer

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, AT BOMBAY

Ref. (CGIT) No. 2/15 of 1976

BETWEEN

Bombay Licensed Measurers Ltd.

AND

Shri A. T. Martyris

In the matter of reinstatement

May it please the Hon. Tribunal :

The parties to the above reference have arrived at the following settlement and pray that an award be made in terms thereof.

1. That Shri A. T. Martyris will be paid the following amounts in full and final settlement of all his claims against the Company :

(a) Company's Provident Fund	Rs.	1,579.45
(b) Ex-gratia payment	Rs.	1,540.00
TOTAL	Rs.	3,119.45

2. That is consideration of the payment made in clause 1 above, Shri Martyris shall have no claim either for reinstatement or remployment with the Company and the order of termination shall stand.

3. That the payment agreed under clause 1 above shall be made to Shri Martyris within a week from the date of the Hon. Court's award.

for Bombay Licensed Measurers Ltd.
Sd/-
B. P. GUNAJI, Jt. Managing Director
(Alfred T. Martyris)

Bombay : 3rd April, 1978.

P. RAMAKRISHNA, Presiding Officer

[No. L-31012(8)/76-D. IV(A)]

NAND LAL, Desk Officer

New Delhi, the 4th May, 1978

S.O. 1488.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Ludhiana, in the industrial dispute between the employers in relations to the management of the Bhakra Management Board and their workmen, which was received by the Central Government on the 29th April, 1978.

BEFORE THE PRESIDING OFFICER OF THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT LUDHIANA

Central Reference No. 1 of 1976

Roshan Lal, Bachan Singh

and Dev Raj

Vs.

M/s. Bhakra Management Board, Nangal Township

(Workman) (Respondent)

APPEARANCES :

Shri Ram Kishan Singh—for the workmen.

Shri Rattan Lal—for the respondent.

AWARD

The Central Government has referred the following industrial dispute between the workmen, Roshan Lal, Bachan Singh and Dev Raj and the management of M/s. Bhakra Management Board, Nangal Township to this court for adjudication under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act 1947 vide No. 42012/3/76/D II(B), dated 21-5-1976 :—

Whether the action of the management of the Bhakra Management Board, Nangal Township, in terminating the services of Shri Roshan Lal, Shri Bachan Singh and Shri Dev Raj, Survey Khalasis, with effect from 30-9-1975, is legal and justified? If not, to what relief are the said workmen entitled?

2. Shri Ram Kishan Singh appeared for the workmen and Shri Rattan Lal for the management.

3. According to the workmen, their services were wrongfully terminated by the management on 30-9-1975 and they have, therefore, claimed reinstatement with continuity of service and full back wages.

4. The case of the management is that the workmen were appointed for a specific period upto 30-9-1975 and so their services were automatically terminated by efflux of time. They have, therefore, objected that the reference is illegal because the management did not terminate the services of the workmen and as such no industrial dispute arose for determination. It is also objected that the reference is bad for non-joinder of necessary party.

5. On these pleadings, following issues were framed :—

ISSUES

1. Whether the reference is unmaintainable as alleged in the preliminary objections of the written statement?
2. Whether the workmen wer appointed for the specified period upto 30-9-1975? If so, its effect?
3. Whether the action of the management in terminating the services of the workmen w.e.f. 30-9-1975 is legal and justified?
4. Relief.

ISSUE NO. 1

6. The objections regarding the maintainability of the reference were not pressed. Therefore this issue is held against the management.

ISSUES NO. 2 & 3

7. The management examined Shri Piara Singh, S.D.O. MW 1, Shri I. P. Puri, XEN MW 2, Shri N. S. Bawa Assistant Law Officer MW 3 and Shri Rattan Lal Personnel Officer MW 4. They also relied upon the documents Ext. M-1 to M-7.

8. The workmen Roshan Lal, Bachan Singh and Dev Raj appeared as WW2, WW4 and WW5 in support of their cases and examined their representative, Shri Ram Kishan Singh WW1 and Shri Jit Ram Clerk WW3. They further relied upon and Shri Jit Ram Clerk WW3. They further relied upon the documents Exs. W-1 to W-5.

9. From the evidence of the parties, it is proved that vide appointment orders Exs. M-1 to M-3, Roshan Lal and Dev Raj claimants were appointed on 9-10-1974 and Bachan Singh on 10-10-1974 for a fixed period upto 31-12-1974. Subsequently vide Ex. M-4 the period of their service was extended upto 28-2-75, vide Ex. M-5 upto 31-3-73, vide Ex. M-6 upto 30-6-75 and vide Ex. M-7 upto 30-9-1975. The document Ex. W-2 shows that the XEN recommended further extension to the claimants but it was refused by the management and consequently their vacancies were filled by adjustment of staff rendered surplus and by a beldar transferred from Nangal Beas Dam Division. It is, therefore, clear that the services of the claimants were automatically terminated after 30-9-1975 by efflux of time.

10. The claimants have raised two objections against this termination. Their first contention is that although they were not given extension after 30-9-1975 but Shri Piare Singh and Sh. Banta Ram junior to them were allowed to cotninue in service. The second contention is that the management did not comply with the provision of Section 25-F of the Industrial Disputes Act, 1947.

11. I find both the contentions unacceptable. It is true that according to Ex. W-2, Shri Piara Singh and Shri Banta Ram were appointed w.e.f. 1-1-1975 and 1-2-1975 respectively subsequent to the appointments of the claimants and they were retained in service upto 31-12-1975 but it was due to the fact that they were employed for a fixed period upto 31-12-1975. As stated by Sh. Piara Singh, S.D.O. MW1 the services of these two employees were also automatically terminated after 31-12-1975. It, therefore, cannot be said that the management violated Sec. 25-G of the Industrial Disputes Act 1947. The last extension was granted to the claimants upto 30-9-1975 vide Ex. M-7 dated 16-6-1975 and to Shri Piara Singh and Shri Banta Ram vide Ex. W-9 dated 9-9-1975 upto 31-12-1975. In both the cases, services of the respective employees were automatically terminated by efflux of time. It would have been a different matter if extension was granted to Sh. Piara Singh and Sh. Banta Ram subsequent to 30-9-1975. In my opinion, therefore, the management did not indulge in any unfair labour practice. No malafide is either alleged or proved against the management.

12. The second contention of the claimants is equally without force. They would have been eligible to the protection of Sec. 25-F only if they had been in continuous service for not less than one year. Admittedly, their fixed period of service was from 9-10-1974 to 30-9-1975 in the case of Roshan Lal and Dev Raj and from 10-10-1974 to 30-9-1975 in the case of Bachan Singh. The period of service of each of the claimants was, therefore, less than one year. Clearly in such circumstances, there is no violation of Sec. 25-F. It is contended on behalf of the claimants that the period of their service was more than 240 days therefore under Sec. 25-B it amounted to one year's continuous service. This submission has no force. Only in that case the actual working days of 240 days are to be considered as one years' service when the workman has worked for 12 calendar months despite interruption in between. In such eventualty the statutue provides that despite interruption in the continuity of service it may be considered continuous service of one year for purpose of Sec. 25-F. Such is not the case in this reference. I am, therefore, of the opinion that Sec. 25-F is not applicable to this case.

13. It is, therefore, held that the termination of services of the claimants by efflux of time was legal and justified and issues are held accordingly.

ISSUE NO. 4

14. Although the management was not guilty of violation of Sec. 25(G) of the Industrial Disputes Act, 1947 but they have certainly violated Sec. 25-H which lays down that where any workmen are retrenched and the employer proposes to take into his employ any persons, he shall, in such manner as may be prescribed, give an opportunity to the retrenched workmen to offer themselves for reemployment and such retrenched workmen shall have preference over other persons. In the present case although the claimants as well as Shri Piara Singh and Sh. Banta Ram junior to them were retrenched as per condition of their service but subsequently as admitted by Shri Piara Singh S.D.O. MW1 Piara Singh and Banta Ram were reemployed without giving an opportunity to the claimants to offer themselves for re-employment. The management should have offered re-employment to the claimants first and on their refusal to Shri Piara Singh and Sh. Banta Ram. However this provision of law was not complied with. I am of the view that on account of violation of Sec. 25-H, the management should pay three months' wages to each of the claimants as compensation. As claimants were employed for a fixed period, the relief of reinstatement is not called for.

15. The result is that the management is directed to pay three months' wages to each of thre claimants and hte parties are left to bear their own costs.

PRITPAL SINGH, Presiding Officer

Dated : 14th March, 1978.

[No. L-42012(3)/76-D. II(B)]

HARBANS BAHADUR, Desk Officer

आदेश

नई दिल्ली, 9 मई, 1978

का० आ० 1489.—ईस्ट डोंगर चिकली कोलियरी, पंच एरिया, वैस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, परासिया, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश, के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उसके कर्मकारों के बीच, जिनका प्रतिनिधित्व एम० पी० राष्ट्रीय कोयला खदान मजदूर संघ करती है, एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और उक्त नियोजकों और उनके कर्मकारों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को माध्यस्थम के लिए निर्देशित करने का करार कर लिया है और उक्त माध्यस्थम करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क की उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यस्थम् करार को, जो उसे 8 मई, 1978 को मिला था, एतद्द्वारा प्रकाशित करती है ।

(करार)

(औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10-क के अधीन)

पक्षकारों के नाम :

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले: 1. डिप्टी सी० एम० आई०/एजेंट, वैस्टर्न, कोल फील्ड्स लिमिटेड, पंच एरिया परासिया उनके ईस्ट डोंगर चिकली कोलियरी से सम्बद्ध ।

कर्मकार का प्रतिनिधित्व करने वाले 1. महा मंत्री, एम० पी० राष्ट्रीय कोयला खदान मजदूर संघ (इंटक) चांदामीटा, डाकखाना चांदामीटा, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश ।

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित औद्योगिक विवाद को मिस्टर न्यायमूर्ति जितेन्द्र नारायण, पीठासीन अधिकारी, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, बम्बई के मध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने का करार किया गया है :—

'विनिर्दिष्ट विवाद ग्रस्त विषय :— क्या वैस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड, पंच एरिया के प्रबंधतंत्र का ई० डी० सी० कोलियरी के 39 भूतपूर्व डी० पी० आर० कर्मचारियों को, प्रत्येक कर्मचारी के आगे उल्लिखित तारीख, जैसाकि अनुबंध में दी गई हैं, के पश्चात् रोजगार प्रदान करने से इंकार करना न्यायोचित है और यदि नहीं तो उक्त भूतपूर्व डी० पी० आर० कर्मचारी किस अनुतोष के हकदार हैं"

(1) प्रबंधतंत्र का नाम और पता : 1. डिप्टी सी० एम० ई० एजेंट वैस्टर्न कोलफील्डस लि० ईस्ट डोंगर चिकली पंच एरिया, परासिया, जिला छिंदवाड़ा (मध्य प्रदेश) ।

(2) कर्मकार का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनियन का नाम और पता : एम० पी० राष्ट्रीय कोयला खदान मजदूर संघ (इंटक) चांदामीटा, डाकखाना चांदामीटा, जिला छिंदवाड़ा (मध्य प्रदेश) ।

(3) अन्तर्ग्रस्त प्रतिष्ठान : ईस्ट डोंगर चिकली कोलियरी, वैस्टर्न कोलफील्डस लि० पंच एरिया ।

(4) यूनियन का नाम मद्द संख्या 2 के अन्तर्गत उल्लिखित ।

(5) उपक्रम में नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या 1456

(6) विवाद द्वारा प्रभावित या सम्भाव्यतः प्रभावित होने वाले कर्मकारों की प्राक्कलित संख्या 39

हम यह करार भी करते हैं कि मध्यस्थ का विनिश्चय हम पर आबद्धकर होगा ।

मध्यस्थ अपना पंचाट दो मास की कालावधि या इतने और समय के भीतर जो हमारे बीच पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ाया जाये, देगा, यदि पूर्व वर्णित कालावधि के भीतर पंचाट नहीं दिया जाता तो माध्यस्थम् के लिए निर्देश स्वतः रद्द हो जायेगा और हम नए माध्यस्थम् के लिए बातचीत करने को स्वतंत्र होंगे ।

पक्षकारों के हस्ताक्षर ह० अपठनीय

1. नियोजक का प्रतिनिधित्व करने वाले डिप्टी सी० एम० ई०, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०, ईस्ट डोंगर चिकली कोलियरी, पंच एरिया, परासिया ।

2. कर्मकार कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले ह० -अपठनीय जनरल सेक्रेटरी, एम० पी० राष्ट्रीय कोयला खदान मजदूर संघ, इंटक० चांदामीटा ।

साक्षी

1. ह० -अपठनीय

2. ह० -अपठनीय

तारीख :

अनुबन्ध

क्रमांक	भूतपूर्व कर्मकार का नाम	पिता का नाम	टी० संख्या	पिछली नियुक्ति की तारीख
1	2	3	4	5
1.	बंगलाल	भीतू	1677	5-6-77
2.	केशराम	भाजू	1678	18-5-77
3.	बिशनू	सेतम	1680	18-5-77
4.	सुभाष	जयदेव	1683	2-4-77
5.	सोबेलाल	हरि	1684	6-6-77
6.	रोशनलाल	रामप्रसाद	1685	26-5-77
7.	मुन्नालाल	महीलाल	1686	31-5-77
8.	लक्ष्मन	सहीलाल	1688	18-5-77
9.	मन्डु	सेहुगलाल	1690	6-6-77
10.	लेखराम	भैयालाल	1692	16-11-76
11.	सुमेरचंद	तिलोकी	1695	6-6-77
12.	सुखदयाल	घूडू	1699	3-6-77
13.	बशीरखान	अहमद खान	1700	18-3-77

1	2	3	4	5
14.	शेख नियाज	शेख मुहम्मद	1703	2-4-77
15	रफीक	मजीद	1704	2-4-77
16.	अंगद	दलसिंह	1730	3-6-77
17.	देवनाथ	वेदवत	1731	6-6-77
18.	शिवराम	हीरामन	1732	7-5-77
19.	हरि	हेमराज	1733	31-5-77
20.	अंगद सिंह	नूरसिंह	1734	6-6-77
21.	महताब	दरसन	1735	6-6-77
22.	रतिलाल	सोभा	1737	31-5-77
23.	गुलाब	छिन्नु	1738	6-6-77
24.	फूलचंद	फक्ली	1739	5-6-77
25.	शेख मुहम्मद	शेख नसरू	1740	3-4-77
26.	मंका	पुसू	1741	4-6-77
27.	धनाई प्रसाद	सोमाई प्रसाद	1742	7-5-77
28.	कमल किशोर	रामसेवक	1743	30-5-77
29.	जगलू	सुखमन	1745	31-5-77
30.	गोपाल	भूरत	1746	22-5-77
31.	शेख रशीद	शेख रहीम	1765	6-6-77
32.	गुरूसेवक	सुमरन	1766	4-6-77
33.	पूनाराम	टेकचद	1767	5-6-77
34.	रमेश	सोहनलाल	1769	18-5-77
35.	सम्मी	शेख वजीर	1770	6-6-77
36.	चेतराम	बिद्दू	1771	18-5 -77
37.	हीराचंद	मौजी	1772	18-5-77
38.	भुवनलाल	टेकचंद	1773	18-5-77
39.	तेजीलाल	गेहरशा	1774	18-5-77

[सं० एल० 22013/1/78-डी० 4(ए)]

नन्द लाल, डेस्क अधिकारी

ORDER

New Delhi, the 9th May, 1978

S.O. 1489.—Whereas an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of East Dongar Chickli Colliery, Pench Area, Western Coalfields Limited, Parasia, District Chhindwara, (M.P.) and their workmen represented by M.P. Rashtriya Koyla Khadan Mazdoor Sangh,

And, whereas, the said employers and their workmen have by a written agreement under sub-section (1) of Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), agreed to refer the said dispute to arbitration and have forwarded to the Central Government a copy of the said arbitration agreement;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (3) of section 10A of the said Act, the Central Government hereby publishes the said agreement which was received by it on the 8th May, 1978.

AGREEMENT

(Under section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947).

Between

NAME OF THE PARTIES :

Representing employers	Dy. CME/Agent Western Coalfields Limited, Pench Area, Parasia in relation to their East Dongar Chickli Colliery.
Representing workman	General Secretary, M.P. Rashtriya Koyla Khadan Mazdoor Sangh (INTUC), Chandametta, P.O. Chandametta, Distt. Chhindwara (M.P.)

It is hereby agreed between the parties to refer the following dispute to the arbitration of Mr. Justice Jitendra Narain, Presiding Officer, Central Government Industrial Tribunal, Bombay.

TERMS OF REFERENCE

Whether the refusal of the management of Western Coalfields Limited Pench Area, to provide employment to 39 Ex-D.P.R. workers of E.D.C. Colliery beyond the date mentioned against each as listed in the annexure is justified and if not, to what relief the said Ex-D.P.R. workers are entitled ?"

1. Name & address of Management	Dy. CME/Agent, Western Coal fields Ltd., East Dongar Chickli, Pench Area, Paracia Distt. Chhindwara (M.P.)
2. Name & address of the Union representing the workman	M.P. Rashtriya Koyla Khadan Mazdoor Sangh (INTUC), Chandametta, P.O. Chandametta, Distt. Chhindwara (M.P.)
3. Establishment involved	East Dongar Chickli Colliery, Western Coalfields Ltd., Pench Area.
4. Name of the Union	Mentioned under item No. 2.
5. Total No. of workers employed in the undertaking.	1456.
6. Estimated number of workers affected or likely to be affected.	39.

We further agree that the decision of the Arbitrator shall be binding on us.

The Arbitrator shall make his award within a period of two months or within such further time as extended by mutual agreement between us in writing. In case the award is not made within the period above mentioned the reference to arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitration.

Signature of the parties :

1. Representing Employer	Sd/- Illegible. Dy. C.M.E./Agent, Western Coalfields Ltd., East Dongar Chickli Colliery, Pench Area, Parasia.
2. Workman/Representing workmen.	Sd/- Illegible. General Secretary, M.P. Rashtriya Koyla Khadan Mazdoor Sangh INTUC, Chandametta.

Witness :

1. Sd/- Illegible.

2. Sd/- Illegible.

ANNEXURE

S. No.	Name of the Ex. workmen	Father's Name	T. No.	Date of last employment
1.	Banglal	Jhitoo	1677	5-6-77
2.	Keshrara	Abboo	1678	18-5-77
3.	Bishnoo	Setam	1680	18-5-77
4.	Subhas	Jaideo	1683	2-4-77
5.	Sobeylal	Hari	1684	6-6-77
6.	Roshanlal	Ramprasad	1685	26-5-77
7.	Munnalal	Mahilal	1686	31-5-77
8.	Laxman	Sahilal	1688	18-5-77
9	Mandoo	Schanglal	1690	6-6-77
10.	Lekhram	Bhaialal	1692	16-11-76
11.	Sumerchand	Tiloki	1695	6-6-77
12.	Sukhdayal	Ghudoo	1699	3-6-77
13.	Bashir Khan	Ahmad Khan	1700	18-3-77
14.	Sk. Niaz	Sk. Mohammad	1703	2-4-77
15.	Rafiq	Majid	1704	2-4-77
16.	Angad	Dalsingh	1730	3-6-77
17.	Deonath	Deonath	1731	6-6-77
18.	Shivram	Hiraman	1732	7-5-77
19.	Hari	Hemraj	1733	31-5-77
20.	Angad Singh	Noorsingh	1734	6-6-77
21.	Mehatab	Darsan	1735	6-6-77
22.	Ratiram	Sobha	1737	31-5-77
23.	Gulab	Chindhoo	1738	6-6-78
24.	Phulchand	Fadali	1739	5-6-77
25.	Sk. Mohammad	Sk. Nasroo	1740	3-4-77
26.	Manka	Pusoo	1741	4-6-77
27.	Dhanai Prasad	Somai Prasad	1742	7-5-77
28.	Kamal Kishor	Ramsewak	1743	30-5-77
29.	Jangloo	Sukhman	1745	31-5-77
30.	Gopal	Moorat	1746	22-5-77
31.	Sk. Rashid	Sk. Rahim	1765	6-6-77
32.	Gurusewak	Sumran	1766	4-6-77
33.	Poonaram	Tekchand	1767	5-6-77
34.	Ramesh	Sohanlal	1769	18-5-77
35.	Sammi	Sk. Wazir	1770	6-6-77
36.	Chaitram	Bittoo	1771	18-5-77
37.	Hirachand	Mouji	1772	18-5-77
38.	Bhuwanlal	Tekchand	1773	18-5-77
39.	Tejilal	Geharsha	1774	18-5-77

[No. L-22013(1)/78-D. IV(A)]
NAND LAL, Desk Officer

New Delhi, the 10th May, 1978

S.O. 1490.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal New Delhi in the industrial dispute between the employers in relation to the management of State Bank of India Jaipur and their workmen over the termination of the service of Shri G. L. Soni, Cashier, Jaipur Branch which was received by the Central Government on the 3-5-78.

132 GI/78—7

BEFORE SHRI MAHESH CHANDRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NEW DELHI

I. D. No. 49 of 1977

BETWEEN

Shri Ganeshi Lal Soni, House No. 6/16, Azad Marg, Roopangarh Road, P.O. Madanganj, Kishan Garh, Ajmer. ..Petitioner.

Versus

The Branch Manager, State Bank of India, Station Road, Jaipur. ..Respondent.

PRESENT :

Shri Ganeshi Lal Soni, the concerned workman.

Shri S. Mishra, Asstt. Law Officer of the Bank.

AWARD

The Central Government as appropriate Government vide its order No. L-12012/177/76-D. II-A dated the 26th April, 1977 made a reference u/s 10 of the I.D. Act, 1947 to this Tribunal in the following terms :

'Whether the action of the management of the State Bank of India, Jaipur in terminating the services of Shri G. L. Soni, Cashier in the Jaipur Branch of the Bank w.e.f. 7-12-1974 is legal and justified ? If not, to what relief is the workman entitled ?"

2. After the reference was registered usual notices were sent to the respective parties and a statement of claim was filed by the workman. A written statement also was filed by the Bank and finally a replication to the written statement was also filed. The case was fixed for admissions and denial of documents when a move for compromise started between the parties and finally the parties have arrived at a settlement. As the settlement was found to be for the benefit of the workman it was ordered to be recorded and accordingly statements of Shri S. Mishra, Asstt. Law Officer of the State Bank of India and Shri G. L. Soni, the workman were recorded on 25-2-1978. The said statement reads as follows :

"The parties have arrived at a settlement. The bank has agreed to appoint Shri G. L. Soni on permanent basis w.e.f. 15-3-1978 at SBI, Jaipur while the workman Shri G. L. Soni gives up his claim for back wages or any other benefit of previous service if any. Parties to bear their costs. Award in terms of this settlement be made and it be directed that the State Bank of India, Jaipur would appoint Shri G. L. Soni on substantive basis w.e.f. 15-3-1978 subject to workman's producing medical fitness certificate from local medical jurist.'

3. In terms of the settlement re-produced above as incorporated in the statement of Asstt. Law Officer of the State Bank of India and the workman, it is awarded that the workman is re-appointed as Cashier on permanent basis w.e.f. 15-3-1978 at the State Bank of India, Jaipur. The workman shall be deemed to have given up his claim for back wages or any other benefit of previous service, if any. This is subject to the workman's producing a medical fitness certificate from the local medical jurist. The parties would bear their own costs.

Dated : the 3rd March 1978.

MAHESH CHANDRA, Presiding Officer

[F. No. L-12012/177/76-D. II A]

R. P. NARULA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978